

स्वदेशी पत्रिका

मूल्य 15/-रु.

ज्येष्ठ-आषाढ़ 2082, जून 2025

A photograph showing a person's hands holding a white sign with the text 'NO GMO' in bold, red and green letters. Below the sign, a gloved hand uses tweezers to place a small plant specimen into a petri dish. The background is a laboratory setting with other petri dishes and plants.

NO GMO

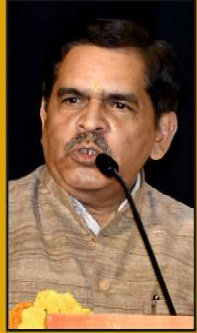
**फिसान और खाद्य सुरक्षा के विरुद्ध हैं
नीति आयोग की सिफारिशें**

स्वदेशी गतिविधियां

शंखनाद, स्वदेशी सुरक्षा एवं स्वावलंबन अभियान

12 जून, 2025 (एनसीयूआई ऑडिटोरियम, नई दिल्ली)

सचित्र झलक



पश्चिम बंगाल प्रांत विचार वर्ग



शंखनाद प्रांत विचार वर्ग





वर्ष-33, अंक-6
ज्येष्ठ-आषाढ़ 2082 जून 2025

संपादक
अजेय भारती

सह-संपादक
अनिल तिवारी

पृष्ठ सज्जा एवं टंकन
सुदामा दीक्षित

कार्यालय

धर्मक्षेत्र, सेक्टर-8, बाबू गेनू मार्ग
रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली-110022
से प्रकाशित

दूरभाष : 011-26184595

स्वदेशी जागरण समिति की ओर से डॉ.
अश्वनी महाजन द्वारा कॉम्प्यूटेट बाइन्डर्स
(प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली-32
से मुद्रित।

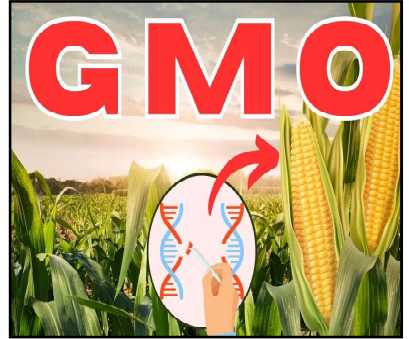
पाठकनामा/उन्होंने कहा **4**
समाचार परिक्रमा **36-38**



तृतीय मुख्य पृष्ठ **39**
चतुर्थ मुख्य पृष्ठ **40**

आवरण कथा - पृष्ठ-06

किसान और खाद्य
सुरक्षा के विरुद्ध हैं
नीति आयोग की
जीएम सिफारिशें
डॉ. अश्वनी महाजन



- 1 मुख्य पृष्ठ
- 2 द्वितीय मुख्य पृष्ठ
- 08 आजकल
युद्ध लबा खींचा तो भारत की आर्थिकी पर भी होगा असर
अनिल तिवारी
- 10 ऑपरेशन सिंदूर
वैश्विक पटल पर भारत का समर्थन
विनोद जौहरी
- 12 ऑपरेशन सिंदूर
भारत की ताकत और विपक्ष की राजनीति का नया द्वंद्व
अजय कुमार
- 14 ऑपरेशन सिंदूर
रक्षा क्षेत्र में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता
दुलीचंद कालीरामन
- 16 विश्लेषण
स्वदेशी का बल
अनिल जवलेकर
- 18 उपलब्धि
साकार हो रहा सामाजिक न्याय का सपना
डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्र
- 20 ज्वलंत मुद्दा
कश्मीर की पुकार
विवेकानंद माथने
- 22 स्वदेशी
आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी जरूरी
अमोल पुसदकर
- 24 देश-विदेश
भारत की कूटनीति का असर: मॉरीशस को मिला चागोस द्वीपसमूह
संजय सक्सेना
- 26 आर्थिकी
घटती गरीबी: बढ़ते धन कुबेर
प्रहलाद सबनानी
- 28 पर्यावरण
प्रकृति बनाम विकास
विजय गर्ग
- 30 योजना
किसानों की आमदनी बढ़ाने का जरिया है पीएम कुसुम योजना
शिवनंदन लाल
- 32 संकल्पना
विकसित भारत की संकल्पना और कौशल विकास
डॉ. जयप्रकाश मिश्र
- 34 विभूतियां
पुण्यस्मरणांजलि: न्यायमूर्ति, लोकमाता अहिल्याबाई होलकर
हेमेन्द्र क्षीरसागर

आसमान पर एयरबस-बोइंग का एकाधिकार

वैश्विक वाणिज्यिक विमानन उद्योग पर केवल दो दिग्गज कंपनियों—एयरबस और बोइंग का दबदबा है। ये दोनों लगभग पूरे बड़े पैमाने के यात्री जेट बाजार को नियंत्रित करती हैं, जिससे अन्य निर्माता प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते। पिछले 15 वर्षों में, हवाई यात्रा में तेज़ वृद्धि के बावजूद, इस क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय नवाचार नहीं हुआ है। इस दौरान कई हाई-प्रोफाइल विमान दुर्घटनाएं भी हुई हैं, जिससे सुरक्षा और गुणवत्ता नियंत्रण को लेकर चिंता बढ़ी है। मजबूत प्रतिस्पर्धा की कमी के कारण एयरलाइनों के पास सीमित विकल्प हैं, और इन कंपनियों में किसी भी प्रणालीगत समस्या का वैश्विक असर हो सकता है।

भारत, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है, ने अब तक अपनी खुद की वाणिज्यिक विमान निर्माण क्षमता विकसित नहीं की है। इसके बजाय, एयर इंडिया और इंडिगो जैसी भारतीय एयरलाइंस अपने बेड़े के विस्तार के लिए पूरी तरह एयरबस और बोइंग पर निर्भर हैं, और हाल के वर्षों में सैकड़ों विमानों के बड़े ऑर्डर दिए हैं। यह निर्भरता इस क्षेत्र में स्वदेशी नवाचार और निर्माण की कमी को उजागर करती है। हालांकि भारत के पास हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के माध्यम से रक्षा एयरोस्पेस में लगभग एकाधिकार है, लेकिन यह विशेषज्ञता वाणिज्यिक क्षेत्र में नहीं आ सकती है।

इसके अलावा, भारतीय एयरलाइन बाजार भी एक पहेली बन गया है, जिसमें 90 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी इंडिगो और टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया ग्रुप के पास है। यह दोहरा एकाधिकार—वैश्विक स्तर पर निर्माण में और घरेलू स्तर पर एयरलाइन संचालन में, उपभोक्ताओं के विकल्पों को सीमित करता है और प्रतिस्पर्धा—आधारित नवाचार को रोकता है। जब तक नए खिलाड़ी सामने नहीं आते, चाहे वैश्विक स्तर पर हों या भारत में, सुरक्षा, तकनीक और यात्री अनुभव में असली प्रगति मुश्किल बनी रहेगी।

विजित कुमार, दिल्ली

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

“धर्मक्षेत्र” शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर-8, रामकृष्णपुरम्,
नयी दिल्ली-110022

दूरभाष : 011-26184595 • ई-मेल:

swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क 'स्वदेशी पत्रिका' दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 150 रुपए

आजीवन सदस्यता शुल्क: 15,00 रुपए

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740

IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

यदि शुल्क जमा करने के उपरान्त भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

कहा-अनकहा



आरावली पर्वतमाला और उसके आगे, पारंपरिक रोपण विधियों के अतिरिक्त, हम नई तकनीकों को प्रोत्साहित करेंगे, विशेष रूप से शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में जहां स्थान की कमी है।

नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री, भारत



भारत ने पूर्व चेतावनी प्रणालियों के विकास में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। समय पर तैयारी को कैलेंडर के साथ एकीकृत किया गया है, सक्रिय रोकथाम और शमन के लिए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित किया गया है।

अमित शाह, गृहमंत्री, भारत



पूर्वोत्तर में हमेशा से ही महिलाएं आगे रही हैं — मछली बाजारों के प्रबंधन से लेकर घर चलाने तक। अब समय आ गया है कि स्वयं सहायता समूह बनाएं, आजीविका का सृजन करें और आत्मविश्वास पैदा करें।

जितेन्द्र सिंह, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री



देश के सभी हितधारकों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए भारत सरकार को नीति आयोग की जीएम आयात सिफारिशों को नज़रअंदाज़ करते हुए जीएम खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध को अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों में तर्क के रूप में और व्यापार युद्ध में ढाल के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए।

डॉ. अश्वनी महाजन, अ.भा. सहसंयोजक, स्वदेशी जागरण मंच

कमतर न आंकिए भारत की विकास यात्रा को

वर्ष 2014 में भारत 2.07 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। 2025 में, हम (मात्र 11 वर्षों में) 4.18 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर की जीडीपी के साथ चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। अंतरराष्ट्रीय तुलना के लिए, एक और आंकड़ा जो सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है, वह है क्रय शक्ति समता के संदर्भ में जीडीपी। क्रय शक्ति समता के पैमाने पर, भारत बहुत पहले ही (वर्ष 2011 में) दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भारत में भारतीय रुपये की क्रय शक्ति डॉलर के बाजार मूल्य से लगभग चार गुना अधिक है। विश्व बैंक के अनुसार 2014 में भारत की जीडीपी (पीपीपी) लगभग 7.4 डॉलर थी, जो 2025 में बढ़कर 17.4 ट्रिलियन डॉलर हो गई है। आज जब यह साबित हो गया है कि डॉलर के बाजार मूल्य के लिहाज से भी भारत की जीडीपी दुनिया में चौथे स्थान पर पहुंच गई है, तो इसका जश्न मनाने के साथ-साथ यह समझना भी जरूरी है कि यह कैसे संभव हुआ और कैसे हम समकालीन दुनिया और इतिहास से सीख लेकर अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत बना सकते हैं।

कुछ लोगों का कहना है कि जापान की प्रति व्यक्ति आय अभी भी भारत की प्रति व्यक्ति आय से 11.6 गुना अधिक है लेकिन अगर हम पीपीपी के आधार पर इन दोनों देशों की प्रति व्यक्ति आय की तुलना करते हैं, तो हम पाते हैं कि जापान की प्रति व्यक्ति आय भारत के प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद का मुश्किल से 4.16 गुना है। एक और दृष्टिकोण यह है कि हमें उपलब्धि का जश्न मनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत अभी भी प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के मामले में 136वें स्थान पर है, और यहां तक कि क्रय शक्ति समता में हम दुनिया के 190 देशों की सूची में 119वें स्थान पर हैं। लेकिन ये संख्याएं जितना छुपाती हैं, उससे कम बताती हैं। जनसंख्या की दृष्टि से 18 बड़े देश हैं, जिनका प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद भारत से अधिक है, जिनकी कुल जनसंख्या लगभग 3.4 अरब है, और शेष 100 देशों की कुल जनसंख्या लगभग 14 करोड़ (0.14 अरब) है। डॉलर के बाजार मूल्य के साथ-साथ पीपीपी के संदर्भ दोनों में प्रति व्यक्ति आय की उच्च वृद्धि दर की बदौलत भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और इसकी रैंकिंग में बेहतरी हो रही है। 2014 में, डॉलर के बाजार मूल्य में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में भारत 190 देशों में से 147वें स्थान पर था; लेकिन 2025 में इसकी स्थिति में सुधार होकर भारत का स्थान 136वां हो गया है। तथा पीपीपी के संदर्भ में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, जो 2014 में 126वें स्थान पर था, अब 190 देशों में 119वें स्थान पर पहुंच गया है।

यही नहीं, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) 2015 (2005-06 और 2011-12 के आंकड़ों पर आधारित) के अनुसार, भारत की लगभग 41.3 प्रतिशत आबादी बहुआयामी रूप से गरीब थी। पोषण, बाल मृत्यु दर, स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्वच्छता और खाना पकाने के ईंधन में प्रमुख अभाव रहे। ग्रामीण गरीबी, शहरी गरीबी से काफी अधिक होने के साथ, भारत में दुनिया के बहुआयामी गरीबों का 30 प्रतिशत से अधिक हिस्सा था। यूएनडीपी की रिपोर्ट के अनुसार 2005-2006 से 2019-2021 तक भारत का बहुआयामी गरीबी सूचकांक (कुल 1.000 में से) 0.283 से गिरकर सिर्फ 0.069 रह गया है; जो शायद बहुआयामी गरीबी का सामना कर रहे देशों में सबसे तेज गिरावट है। दिलचस्प बात यह है कि यूएनडीपी ने इस उपलब्धि के लिए भारत की भूरी भूरी प्रशंसा भी की। अगर हम अत्यधिक गरीबी (2.15 अमेरिकी डॉलर की दैनिक आय वाले लोग) को देखें, तो विश्व बैंक (2022) और आईएमएफ के अनुसार, भारत ने वैश्विक मानकों के अनुसार अत्यधिक गरीबी को लगभग समाप्त कर दिया है। 2014 में, अनुमानतः भारत की 12.3 प्रतिशत आबादी अत्यधिक गरीबी में रहती थी, यानी लगभग 170 मिलियन लोग। अनुमान है कि 2024-25 तक अत्यधिक गरीबी घटकर लगभग 3-4 प्रतिशत रह जाएगी, यानी अनुमानतः देश में 40-55 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी में रहते हैं। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी), मुफ्त भोजन, बुनियादी सेवाओं जैसे स्वच्छता, स्वास्थ्य, बैंकिंग और बिजली तक पहुंच के कारण यह संभव हो सका है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि जीडीपी संख्या जो दर्शाती है कि भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है लेकिन सरकार अभी भी 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन वितरित कर रही है, एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। लेकिन यहां हमें यह समझना होगा कि मुफ्त भोजन का वितरण केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, यहां तक कि अमेरिका और ब्रिटेन सहित अधिकांश विकसित देशों में भी उनकी आबादी का एक बड़ा हिस्सा मुफ्त राशन का लाभ लेता है।

हालांकि, यह जश्न मनाने का कोई कम कारण नहीं है कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है; और आने वाले 2-3 वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए नियत है; यह हमें भारत की उपलब्धियों पर गर्व करने के लिए और अधिक कारण देता है, चाहे वह प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग के संदर्भ में हो या बहुआयामी गरीबी और अत्यधिक गरीबी दोनों को कम करने में इसकी उपलब्धियों के संदर्भ में हो; और वह भी अन्य विकासशील देशों की तुलना में बहुत तेजी से। हालांकि अभी लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन अब तक की यात्रा भी उल्लेखनीय रही है। इस तथ्य को भी ध्यान में रखना चाहिए ताकि हम सही रास्ते पर चलते रहें।

राहत के नाम पर आफत के आयात का मसौदा रद्द करे सरकार

किसान और खाद्य सुरक्षा के विरुद्ध हैं नीति आयोग की जीएम सिफारिशें

कुछ दिनों पहले नीति आयोग ने एक वर्किंग पेपर में भारत सरकार से सिफारिश की थी कि वर्तमान में प्रस्तावित भारत-अमेरिका व्यापार समझौते में आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) कृषि उत्पादों के आयात की अनुमति दी जानी चाहिए। इसमें नीति आयोग ने मक्का और सोयाबीन जैसी फसलों का भी विशेष रूप से जिक्र किया है। वर्किंग पेपर में यह भी सुझाव दिया गया है कि सरकार को उन कृषि उत्पादों के आयात को भी खोलने की पेशकश करनी चाहिए, जो या तो भारत में पैदा नहीं होते हैं या उनका उत्पादन इतना कम है कि उनके आयात का किसानों पर कोई खास असर नहीं होगा। इस संबंध में वर्किंग पेपर में चावल, काली मिर्च, सोयाबीन तेल, झींगा, चाय, कॉफी, डेयरी उत्पाद, पोल्ट्री, सेब, बादाम, पिस्ता आदि का उदाहरण दिया गया है, जिनके आयात को खोलने की सिफारिश की गई है।

नीति आयोग द्वारा इस वर्किंग पेपर में की गई सिफारिशों के बाद भारतीय किसान संघ (बीकेएस) समेत किसान संगठनों की ओर से तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं और इस संबंध में नीति आयोग की कड़ी आलोचना की गई है और कहा गया है कि ये सुझाव पूरे देश और खास तौर पर किसानों के हितों के खिलाफ हैं। मसलन, बीकेएस ने कहा है कि ये सुझाव देश और किसानों के हितों के खिलाफ हैं। बीकेएस का यह भी कहना है कि नीति आयोग ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए हैं, जो कि सुखद संकेत नहीं है।

दूसरी ओर, खबर यह भी है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता ठप्प पड़ गई है, क्योंकि सरकार अमेरिका की जीएम और अन्य कृषि उत्पादों के लिए बाजार खोलने की मांग मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में नीति आयोग का यह वर्किंग पेपर सरकार के रुख को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। इसका यह भी अर्थ लगाया जा सकता है कि नीति आयोग सरकार के जीएम विरोधी रुख को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। ये दोनों ही स्थितियां देश के लिए अच्छी नहीं हैं। पहले भी नीति आयोग ने जीएम का समर्थन किया था। यह पहली बार नहीं है कि नीति आयोग ने जीएम फसलों की वकालत की हो। इससे पहले भी प्रोफेसर अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में आयोग ने जीएम फसलों के पक्ष में एक रिपोर्ट जारी की थी। उस समय भी इसका कड़ा विरोध हुआ था।

देश में जीएम फसलों का विरोध लंबे समय से हो रहा है। जीएम के समर्थक लगातार जीएम के पक्ष में प्रयास करते रहे हैं। हालांकि, जीएम के प्रबल विरोध और उसके ठोस तर्कों के कारण जीएम समर्थक सफल नहीं हो पाए। उनके विरोध के कई कारण हैं:

पहली वजह यह है कि ज्यादातर जीएम फसलें शाकनाशी के प्रति सहनशील होती हैं। यानी जब ये फसलें उगाई जाती हैं, तो आस-पास की सभी जड़ी-बूटियाँ निर्धारित शाकनाशियों के इस्तेमाल से नष्ट की जा सकती हैं और जीएम फसलें प्रभावित नहीं होतीं। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर (आईएआरसी) ने ग्लाइफोसेट को "संभवतः मनुष्यों के लिए कैंसरकारी" के रूप में वर्गीकृत किया है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि जब जीएम फसलों के उत्पादन के दौरान इन शाकनाशियों का इस्तेमाल किया जाता है, तो उनके कुछ अवशेष उन कृषि उत्पादों और मिट्टी में रह जाते हैं, जो कैंसर का कारण बन



देश में जीएम फसलों का विरोध लंबे समय से हो रहा है। जीएम के समर्थक लगातार जीएम के पक्ष में प्रयास करते रहे हैं। हालांकि, जीएम के प्रबल विरोध और उसके ठोस तर्कों के कारण जीएम समर्थक सफल नहीं हो पाए। उनके विरोध के कई कारण हैं।

— डॉ. अश्वनी महाजन

सकते हैं। आँकड़े बताते हैं कि अमेरिका में प्रति एक लाख की आबादी पर 350 कैंसर रोगी हैं, जबकि भारत में यह आँकड़ा प्रति एक लाख पर 100 है। इसका एक कारण अमेरिका में जीएम फसलों में शाकनाशियों का अत्यधिक इस्तेमाल भी है।

वैसे तो भारत में जीएम खाद्य उत्पादों के इस्तेमाल और आयात पर रोक है, लेकिन खाद्य तेलों की कमी के कारण पिछले कुछ समय से अमेरिका और दूसरे देशों से खाद्य तेलों का आयात बढ़ रहा है, जिसमें से कुछ मात्रा में जीएम खाद्य तेल भी अनजाने में आयात हो रहे हैं। भारत सरकार पहले भी इस बात को स्वीकार कर चुकी है। इसके कारण भारत में कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जहां वर्ष 2000 में कैंसर के केवल 8 लाख मरीज थे, वहीं वर्ष 2024 तक इनकी संख्या 15 लाख तक पहुंच चुकी है। जीएम खाद्य तेलों की खपत भी इसका एक कारण हो सकता है।

जीएम फसलों के आयात के विरोध का दूसरा कारण यह है कि देश के कानून के अनुसार जीएम फसलों के उत्पादन और आयात को देश में कानूनी रूप से अनुमति नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हमारे नियमों का सम्मान करते हुए अन्य भागीदार देशों द्वारा इस संबंध में कोई विवाद नहीं उठाया जा सकता है। डब्ल्यूटीओ के नियमों के तहत हर देश को अपने नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए दूसरे देशों से आने वाले सामान पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार है।

अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार, अमेरिका से आने वाले जीएम उत्पादों को देश में प्रवेश करने से रोकना संभव है। चूंकि भारतीय किसान पहले से ही अपनी उपज के लिए लाभकारी मूल्य न मिलने के कारण आर्थिक नुकसान उठा रहे हैं, ऐसे में यदि सस्ते जीएम उत्पादों को आयात करने की अनुमति दी गई तो हमारे किसानों को नुकसान होगा

और ऐसी स्थिति में यदि किसान खेती करना बंद कर देंगे तो देश की खाद्य सुरक्षा ही खतरे में पड़ सकती है।

तीसरा, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा बनाए गए खाद्य सुरक्षा नियमों के तहत जीएम उत्पादों की बिक्री संभव नहीं है, जिसके अनुसार खाद्य उत्पादों में एक सीमा से अधिक जीएम तत्व नहीं हो सकते। ऐसे में देश में जीएम उत्पादों के आयात की अनुमति देने के बाद वे भारत की खाद्य शृंखला का हिस्सा बन जाएंगे, जिससे न केवल देश के नियमों का उल्लंघन होगा, बल्कि नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए भी खतरा पैदा होगा।

उपरोक्त कारणों के अलावा, चौथा कारण, जो देश में जीएम उत्पादों के आयात के खिलाफ जाता है, वह यह है कि जिन जीएम उत्पादों के आयात की सिफारिश नीति आयोग ने की है, उनका उपभोग आमतौर पर अमेरिका में मनुष्य द्वारा नहीं किया जाता है।

अमेरिका में मक्का और सोया का इस्तेमाल ज्यादातर या तो पशु आहार के रूप में किया जाता है या फिर इथेनॉल बनाने के लिए। गौरतलब है कि अमेरिका में 40 से 50 प्रतिशत जीएम मक्का का इस्तेमाल पशु आहार के रूप में, 30 से 40 प्रतिशत इथेनॉल बनाने में और केवल 10 प्रतिशत खाद्य प्रसंस्करण में किया जाता है। इसी तरह सोया का इस्तेमाल भी ज्यादातर पशु आहार के रूप में किया जाता है। भारत की खाद्य शृंखला में ऐसे जीएम उत्पादों का शामिल होना न केवल देशवासियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है बल्कि इस देश के लोगों का अपमान भी है।

यद्यपि नीति आयोग में बैठे लोगों द्वारा लगातार जीएम उत्पादों की वकालत की जाती है, लेकिन देश में किसानों और प्रबुद्ध वैज्ञानिकों द्वारा विरोध तथा इस संबंध में न्यायिक अनुमति न मिलने के कारण वे सफल नहीं हो

पाते हैं। ऐसी स्थिति में, जब अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है, तथा भारत में जीएम खाद्य पर प्रतिबंध को किसानों और डेयरी के हितों की रक्षा के लिए ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, नीति आयोग द्वारा ऐसी सिफारिशें किसानों, लोगों के स्वास्थ्य और देश की खाद्य सुरक्षा के प्रति उनकी उदासीनता का परिचायक है।

इसके अलावा, हमें यह समझने की जरूरत है कि भारत लगभग 50 बिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य के कृषि खाद्य उत्पादों का निर्यात करता है, और भारतीय खाद्य का एक बड़ा आकर्षण यह है कि यह गैर-जीएम टैग वाला है।

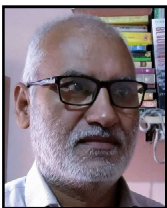
जैसे ही जी.एम. हमारी खाद्य शृंखला में प्रवेश करेगा, हम अपने निर्यात बाजारों का एक बड़ा हिस्सा खो सकते हैं, क्योंकि मध्य पूर्वी देश यूरोप और कई अन्य देश जी.एम. खाद्य उत्पादों के आयात की अनुमति नहीं देते हैं। शायद, नीति आयोग भारत में जी.एम. आयात और उत्पादन से जुड़े इस महत्वपूर्ण जोखिम को ध्यान में रखने में विफल रहा है।

भारत सरकार को नीति आयोग की इन सिफारिशों को नज़रअंदाज़ करते हुए जीएम खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध को अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों में तर्क के रूप में और व्यापार युद्ध में ढाल के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए तथा देश के किसानों, डेयरी, खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा लगता है कि देश के अधिकांश कृषि संगठनों के विरोध के बावजूद जीएम समर्थक किसी भी कीमत पर देश में जीएम के आयात की अनुमति देना चाहते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि एक बार देश में जीएम के आयात की अनुमति मिल गई तो यह जीएमओ को कृषि में लाने का रास्ता साफ कर देगा। हमें ऐसे किसी भी प्रयास से सावधान रहने की जरूरत है। □□

युद्ध लंबा खींचा तो भारत की आर्थिकी पर भी होगा असर

इजराइल और ईरान के बीच छिड़े युद्ध में अमेरिका के कूद आने के बाद अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और भू-राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। भारत सहित दुनिया के कई देशों ने ईरान पर अमेरिका के हमले के बाद युद्ध के बड़े क्षेत्र में फैलने की आशंका को देखते हुए कूटनीतिक समाधान तलाशने और संयम बरतने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौजूदा युद्ध पर चिंता जताते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भारत हमेशा शांति और मानवता के पक्ष में रहा है। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के संतुलनकर्ताओं से बातचीत कर स्थाई हल निकाले जाने पर बल दिया है।

लगातार बदलते वैश्विक परिदृश्य के साथ कदम ताल करते हुए हाल के बरसों में भारत और इजराइल करीब आए हैं। सुरक्षा और तकनीक के क्षेत्र में भारत और इजराइल के बीच गहरा सहयोग प्राप्त है। वर्ष 2023 में हमारा हमले पर भारत ने कड़े शब्दों में प्रतिक्रिया दी थी। पहलगाम हमले के बाद इजराइल उन देशों में था जो भारत की आत्मरक्षा के अधिकार के साथ खुलकर सामने आया था। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि ईरान के साथ भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध हैं। भारत और ईरान क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, भू राजनीतिक मसलों के साथ-साथ ऊर्जा जैसे मुद्दों पर साथ खड़े हैं। ऐसे में युद्ध के मद्देनजर भारत का भी बहुत कुछ दांव पर लगा है। भारत के लिए मध्य एशिया का लिंक है चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट। चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट भारत को अफगानिस्तान मध्य एशिया और ईरान तक सीधी पहुंच देता है। भारत ने अच्छा खासा निवेश भी किया है। चीन की बीआरआई परियोजना के मद्देनजर भारत के लिए यह एक अहम रणनीतिक प्रोजेक्ट है। इन सब को देखते हुए भारत पूरे घटनाक्रम पर करीब से नजर रखे हुए हैं क्योंकि इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बरकरार रखने में उसकी हिस्सेदारी है। मालूम हो कि मध्य पूर्व के देशों में लगभग एक करोड़ भारतीय लोग रहते हैं और वहां भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं। ऐसे सभी भारतीयों की सुरक्षा और कल्याण भारत सरकार के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। हालांकि ईरान इजराइल युद्ध शुरू होने के बाद कई भारतीय छात्रों के साथ-साथ नेपाल और श्रीलंका के छात्रों और नागरिकों को भी ईरान से सुरक्षित निकाला गया है और आगे भी भारत की ओर से ऐसे प्रयास जारी रखने के संकेत सरकार की ओर से मिले हैं। भारत की लगभग 60 प्रतिशत से ऊपर की ऊर्जा जरूरतें इस क्षेत्र से पूरी होती हैं ऐसे में अगर कोई भी अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न होती है तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा को भी इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। इजराइल हमारा युद्ध और हुती विद्रोहियों के कारण शिपिंग मार्ग पहले से ही बाधित थे, अब ईरान इजराइल युद्ध के कारण होरमुज जलडमरूमध्य के प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। इससे पश्चिम एशियाई देशों के साथ भारत के आयात-निर्यात में बाधा खड़ी हो सकती है।



भारत इजराइल और ईरान दोनों के पांच बड़े व्यापारिक साझेदारों में शामिल है। युद्ध का असर दोनों देशों के साथ आयात और निर्यात पर पड़ेगा।

—अनिल तिवारी

तकरीबन 500 साल पहले बाबर ने अपनी किताब में एक जगह लिखा था कि उसे अपने देश के बादाम बेचने के लिए उन्हें होरमुज जल संधि के बंदर अब्बास तक ले जाना पड़ता है, जिसका रास्ता बहुत कठिन और खर्चीला है, फिर भी वह व्यापारिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आज लगभग पांच शताब्दी बीत जाने के बाद ईरान-इजराइल के वर्तमान युद्ध के कारण होरमुज जलडमरूमध्य का महत्व फिर से बढ़ गया है।

ईरान और ओमान के बीच होरमुज जलडमरूमध्य स्थित है, जो लगभग 40 किमी. चौड़ी समुद्र पट्टी है, जिसके जरिए दुनिया का 20 प्रतिशत कच्चा तेल और पेट्रोलियम पदार्थ निर्यात होते हैं। इस मार्ग से मुख्य रूप से सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर, इराक और ईरान के माल निर्यात होते हैं। इस समुद्री मार्ग के अवरुद्ध होने पर विश्वव्यापी कच्चे तेल की सप्लाई पर असर पड़ेगा जिससे उसकी कीमतों में वृद्धि होने की संभावना है, जो गैसोलीन एवं अन्य वस्तुओं की कीमतों में भी बढ़त कर सकती हैं, और मुद्रास्फीति की स्थिति ला सकती है। समुद्र पट्टी के नीचे सबमैरीन केबल से विश्व की 95 प्रतिशत इंटरनेट और डाटा ट्रैफिक जाती है, जिसमें भारत भी सम्मिलित है। यह इस्त्राइल और होरमुज जलडमरूमध्य से लगी हुई है। यूरोपीय गेटवे, फाइबर ऑप्टिक लिंक आदि इस कॉरिडोर से होकर जाती है। यूरोप, एशिया और अफ्रीका के लिए यह डिजिटल लाइफलाइन है। युद्ध में बमबारी के कारण यह खतरे में पड़ सकती है, जिसका विकल्प बहुत महंगा होगा और बहुत सारे देश इससे प्रभावित होंगे। भारत की डिजिटल इकॉनमी, जो देश की जीडीपी में 245 बिलियन डॉलर का योगदान करती है, दुष्प्रभावित हो सकती है। ईरान अपने आप को परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) से अलग कर सकता है, और अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सहयोग करना बंद कर सकता है, इससे परमाणु युद्ध की आशंका बढ़ सकती है।

इजराइल के साथ भारत का घनिष्ठ संबंध है। ईरान के साथ भी उसके संबंध पाकिस्तान के साथ अधिक निकटता के बावजूद कुल मिलाकर लाभकर ही रहे हैं। ईरान के चाबहार बंदरगाह के निर्माण में भारत ने भारी निवेश किया है। यह पाकिस्तान को दरनिकार कर अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के लिए भारत का गेटवे है, भारत के अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण यातायात

गलियारे का हिस्सा है। भारत के बासमती चावल का ईरान सबसे बड़ा खरीदार है। इजराइल से भारत रक्षा सामग्री और आधुनिकतम मारक रक्षा यंत्रों की भारी मात्रा में खरीदारी करता है। इसके अतिरिक्त, डायमंड, केमिकल्स, मशीनरी और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स पदार्थ भी आयात करता है। भारत से इजराइल जो सामान खरीदता है, उनमें हीरा-मोती, सेमीप्रोसेस्ड स्टोन, इंजीनियरिंग गुड्स और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक शामिल हैं। 2024-25 में भारत ने इजराइल से जितना सामान खरीदा उससे 16 बिलियन डॉलर अधिक का निर्यात किया।

ईरान से भारत कच्चा तेल, ऑर्गेनिक एवं इनॉर्गेनिक केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, प्लास्टिक एवं मेवे (बादाम, पिस्ता, छुहारा आदि) खरीदता है। ईरान को बासमती चावल के अलावा चाय, फर्टिलाइजर, आयरन एंड स्टील, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, प्रेशर मिनरल्स, पॉलिएस्टर यार्न और फाइबर आदि निर्यात करता है।

भारत इजराइल और ईरान दोनों के पांच बड़े व्यापारिक साझेदारों में शामिल है। युद्ध का असर दोनों देशों के साथ आयात और निर्यात पर पड़ेगा। भारत से जो माल ईरान जा रहा है, उसका भुगतान पहले से ही देर से मिल रहा है, अब और देर होने की संभावना है, जिसके कारण भारत के व्यापारी और सरकारी कंपनियां विश्व के दूसरे बाजारों की तलाश में लग लग गए हैं। कच्चे तेल के सप्लाई के लिए भी भारत की कंपनियां अन्य देशों की ओर रुख करने को मजबूर हो सकती हैं। यद्यपि ईरान पर इस मामले में भारत की निर्भरता अधिक नहीं है, इस कारण देश में पेट्रोल और पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति पर इजराइल-ईरान युद्ध का ज्यादा अवसर नहीं पड़ेगा।

फिर भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अस्पष्ट टैरिफ नीति के कारण पहले से ही संकट में घिरी वैश्विक

अर्थव्यवस्था पर इस युद्ध के कारण आपूर्ति श्रृंखला की नई आपदा आ खड़ी हुई है। युद्ध से वैश्विक वित्त बाजार प्रभावित हो रहा है। जिस दिन इजराइल ईरान युद्ध शुरू हुआ पूरी दुनिया के स्टॉक एक्सचेंज में कीमतों में भारी गिरावट हुई। भारतीय शेयर बाजार में बीएसई सूचकांक 1300 अंक नीचे चला गया। आपूर्ति श्रृंखला में बाधा की आशंका से कच्चे तेल की वैश्विक कीमत तेजी से ऊपर की ओर भाग रही है। तेल कंपनियों एवं वित्तीय कंपनियों के शेयरों में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। शेयर बाजार की निवेश में कमी आई है और मंदी का माहौल लगातार बढ़ता जा रहा है। शेयर और म्यूचुअल फंड की जगह उपभोक्ता निवेशक सोने चांदी में निवेश ज्यादा सुरक्षित मान रहे हैं।

कुल मिलाकर ईरान इजराइल युद्ध शुरू होने के बाद से मध्य पूर्व में संघर्ष की आशंका बढ़ी है जिसका असर तेल की कीमतों पर दिखने लगा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमत 74.40 प्रति बैरल हो चुकी है। वही चूंकि भारत के दोनों देशों से संबंध अच्छे हैं इसलिए इसलिए दोनों के साथ संतुलन बनाए रखने की कूटनीति चुनौती पूर्ण है। ईरान का चाबहार बंदरगाह सामरिक दृष्टि से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रोजेक्ट में भारत बड़ा हिस्सेदार भी है। सऊदी अरब यूएई ओमान बहरीन कतर कुवैत ईरान और इजराइल में लगभग एक करोड़ भारतीय रह रहे हैं। इन देशों में रहने वाले भारतीय लाखों डॉलर की राशि भारत भेजते हैं जिससे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होता है। युद्ध के फैलने की स्थिति में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर भी सीधा असर पड़ेगा। युद्ध की स्थिति में भारत की सुरक्षा चुनौतियों भी बढ़ सकती हैं। राजनीति शास्त्र और सैन्य विज्ञान का स्थापित सत्य है कि जब पावर बैक्यूम बढ़ता है तो नॉन स्टेट एक्टर्स अपनी जगह बनाने के लिए गतिशील हो जाते हैं। □□

वैश्विक पटल पर भारत का समर्थन

संप्रति वैश्विक परिदृश्य में ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में पाकिस्तान से उपजे भारत विरोधी विमर्श को विश्व भर में प्रचारित करने के द्वेषपूर्ण समाचार चिंताजनक हैं और तथ्यों के आधार पर उनका तुरंत खंडन और भी आवश्यक। पाकिस्तान के मिथ्या विमर्श विभिन्न विदेशी मीडिया चैनलों में पाकिस्तानी पत्रकारों के कारण तीव्रता से फैले हैं, और उतनी ही तीव्रता से उनका खंडन भारत के विश्व भर में तथ्यात्मक विमर्शों के कारण हुआ है। पाकिस्तान के भीतर से पाकिस्तान की सरकार और सेना के दमन के रोष से उपजे आक्रोश ने भी पाकिस्तानी विमर्श को झुठलाया है। पाकिस्तान की परमाणु बम की धमकी भी मिट्टी में मिल गयी और उसका चीनी सुरक्षा कवच भी धराशाई हो गया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पाकिस्तानी सरकार और सेना सकते में हैं और उनके पास अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे देशों से गुहार लगाने के अलावा कुछ नहीं बचा।

जब भी ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा हो, तो उस चर्चा का आरंभ 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पाकिस्तान की सेना द्वारा भेजे गए आतंकवादियों द्वारा पहलगाम में धर्म पूछकर हिंदु पर्यटकों की हत्या की चर्चा पहले होनी आवश्यक है।

विश्व भर में भारत विरोधी मीडिया का विमर्श ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को पीड़ित और भारत को आक्रांता के रूप में परिलक्षित करने का है। इस षड्यंत्र का एक अंश और दंश हमारे एक विशिष्ट राजनीतिक वर्ग में व्याप्त है जो भारत को पराजित दिखाने और भारतीय सेना पर प्रश्नचिह्न खड़े कर रहा है और विदेशी मीडिया के भारत विरोधी विमर्श को ही भारत में आगे बढ़ा रहा है।

वास्तविकता यह है कि विश्व भर में अमेरिका और रूस सहित 123 देशों ने भारत का समर्थन किया है और पहलगाम में आतंकवादी हमलों की निंदा की है और ये सभी देश ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के पक्ष में खड़े हैं।

चीन, तुर्किये और अज़रबैजान ने स्पष्ट रूप से पाकिस्तान का साथ दिया है। अमेरिका के संदर्भ में पाकिस्तान सरकार के प्रधानमंत्री और नेता एवं मीडिया स्वयं अमेरिका की ओर से मध्यस्थता की बात कर रहे हैं और साथ ही यह भी स्वीकार कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के मात्र अड़तालीस घंटों में पाकिस्तानी का रक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर के ध्वस्त होने, भारी संख्या में पाकिस्तानी आतंकवादियों की मृत्यु और नौ बड़े आतंकी लांच पैड के नष्ट होने से तिलमिलाया पाकिस्तान अमेरिका से युद्ध विराम कराने की गुहार लगा रहा था।

पाकिस्तान के संदर्भ में चीन और अमेरिका की गुथी बहुत उलझी हुई है। इस समय पाकिस्तान सरकार, नेता और मीडिया अमेरिका के भरोसे ही अपनी रक्षा की दुहाई दे रहे हैं और चीन पाकिस्तान में भारतीय मिसाइलों, एअर डिफेंस सिस्टम, सेना के तीनों अंगों की संयुक्त कमान और आक्रामक कार्यवाही से अपने आधुनिकतम रक्षा प्रणालियों के असफल होने से तिलमिलाया हुआ, पाकिस्तान में सीपैक और विभिन्न परियोजनाओं में भारी निवेश के कारण पाकिस्तान के साथ खड़ा है और भारत के भू-भाग पर अनधिकृत कब्जे को लेकर और पाक अनधिकृत काश्मीर पर सीपैक को लेकर चिंता के कारण भारत विरोध उसकी विवशता है। तुर्किये मुस्लिम देशों का खलीफा बनने का महत्वाकांक्षी हैं और अज़रबैजान



भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के साथ बहुत सशक्त सैन्य शक्ति वाला आत्मनिर्भर देश है। इसलिए बेहतर है कि भारत की ओर कोई आंख उठा कर भी न देखें, यदि हमारी भृकुटी तन गयी तो तांडव हो जायेगा और भूगोल बदल जायेगा।
— विनोद जौहरी

उनका पिछलग्गू। पूर्व में भारत द्वारा अज़रबैजान के शत्रु देश अर्मेनिया को भारत ने समर्थन दिया था, इसी कारण अज़रबैजान का भारत विरोध उसकी ही परिणति है।

अफगानिस्तान की भारत से निकटता के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद ने आतंकी देश पाकिस्तान को आतंक नियंत्रण की समिति का दायित्व सौंपा है जो निरर्थक है, क्योंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान का धुर विरोधी है और दोनों देश आपसी सीमा विवादों में खूनी संघर्ष कर रहे हैं।

दूसरी तरफ विभिन्न देशों में अमेरिकी टैरिफ व्यवस्था को लेकर विरोध है। चीन के विस्तारवादी और संरक्षणवादी व्यवहार को लेकर उसका अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ विरोध है। इसमें बांग्लादेश का कोण भी प्रासंगिक है जो अपने भयंकर संकट में पाकिस्तान के सहारे भारत विरोधी व्यवहार दिखा रहा है। अमेरिका परोक्ष एवं अपरोक्ष रूप से पाकिस्तान को चीन को टक्कर देने और उसका विरोध करने के उद्देश्य से अपने प्रभाव में लाने के लिए उत्सुक हो सकता है परंतु यह सब घटनाक्रम इतना उलझा हुआ और क्षणिक है कि प्रमाणिक रूप से अमेरिका के संदर्भ में कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता।

भारत ने विभिन्न देशों में अपने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजे जिन्होंने राष्ट्र धर्म निभाते हुए विश्व के सामने भारत का पक्ष रखा और पाकिस्तान द्वारा आतंकी हमलों और आपरेशन सिंदूर के तथ्यों को उनके सामने रखकर पाकिस्तान के दुष्प्रचार को ध्वस्त किया। अब यह प्रतिनिधिमंडल विदेशी यात्राओं से वापस आकर और भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दिए हैं।

समानांतर रूप से पाकिस्तान ने भी अपने प्रतिनिधिमंडल कुछ देशों में भेजे परंतु उनको अपने नकारात्मक विमर्श, दुष्प्रचार और आतंकी हमलों के

कारण समर्थन नहीं मिला।

प्रेसवार्ता में हमारे प्रतिनिधिमंडलों ने विदेशों में अपनी सफल यात्रा के वर्णन किये हैं वहीं पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडलों के असफल झूठे प्रयासों का भी उल्लेख किया है।

इस पूरे घटनाक्रम में सिंधु नदी समझौते के निरस्त होने से पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था चौपट होने और उसका अस्तित्व संकट में आने से पाकिस्तान विश्व भर में अपने पक्ष में समर्थन के लिए गुहार लगा रहा है। ज्ञात को कि पाकिस्तान के अस्सी प्रतिशत जल आपूर्ति भारत की नदियों से होती है। आपरेशन सिंदूर के चलते पाकिस्तानी नेता सिंधु नदी में खून बहाने की धमकी दे रहे थे, आज पानी के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि इस पर वार्ता नहीं होगी और जो वार्ता होगी वह केवल पाक अनधिकृत जम्मू-कश्मीर पर होगी।

पाकिस्तान के बड़े भूभाग बलोचिस्तान और पाक अनधिकृत काश्मीर में स्वतंत्रता के लिए भारी जनक्रोध और लड़ाई और सिंध में पाकिस्तान द्वारा दुराग्रही जल नहरों की खुदाई और दमनकारी नीतियों के कारण भारी विरोध लंबे समय से चल रहा है। इस सब के बावजूद मुस्लिम देश भी पाकिस्तान के समर्थन में नहीं हैं क्योंकि पाकिस्तान आतंक का वैश्विक केंद्र बना हुआ है। रूस भारत का विश्वस्त मित्र देश है।

‘इंडिया एलोन’ जैसा विमर्श भारत विरोधी मीडिया में चलाया जा रहा है जिसकी स्पष्ट उपस्थिति भारत में भी है। आज भारत के कुछ विशिष्ट वामपंथी विचारधारा के समाचार पत्रों की स्थिति यह है कि वह चीन के विरुद्ध जनमानस के आक्रोश को नहीं प्रकाशित करते हैं और ऑपरेशन सिंदूर में भारत को पराजित और विश्व में अलग-थलग दिखाने का प्रयास करते हैं। भारत विरोधी विदेशी मीडिया भारत-पाकिस्तान के संदर्भ में

अमेरिका को सम्मिलित करके अनर्गल समाचार छापता है और विमर्श संचालित करता है। आज अमेरिका और चीन भारत को अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखते हैं। विश्व के बड़े देश और विशेषकर युरोपीय और मुस्लिम देश भारत के साथ संबंधों को नये आयाम दे रहे हैं।

पाकिस्तान को कभी समझ नहीं आयेगा कि उसका समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे देश उसका अपने हित में इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान के आतंकियों को उन मददगार देशों ने ही विदेशों में एक्सपोर्ट किया है।

झूठे विमर्शों से धरातल की वास्तविकता नहीं बदलती। संपूर्ण भारत के जनमानस ने आपरेशन सिंदूर से भारत का साथ दिया है और भारतीय सेना की विजय में अपना गौरव देखा है। कतिपय विरोधी और नकारात्मक विमर्श से धरातल की परिस्थितियां नहीं बदलतीं और चीन – तुर्किये – अज़रबैजान न तो पाकिस्तान को बदल सकते हैं और न उसकी बदहाली को, न भारत की ताकत को हरा सकते हैं और न उसको वैश्विक पटल पर अलग-थलग कर सकते हैं। भारत विरोधी मीडिया और इकोसिस्टम को भारत में चलाने वालों को भारत की जनता ने करारा जवाब दिया है और विदेशों में कई आमचुनावों में जनमानस ने मुस्लिम तुष्टिकरण और वामपंथी विचारधारा के राजनीतिक दलों को सत्ताच्युत किया है। भारत ने अमेरिका को अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है और किसी भी मध्यस्थता के प्रयास की संभावना को नकार दिया है। भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के साथ बहुत सशक्त सैन्य शक्ति वाला आत्मनिर्भर देश है। इसलिए बेहतर है कि भारत की ओर कोई आंख उठा कर भी न देखें, यदि हमारी भृकुटी तन गयी तो तांडव हो जायेगा और भूगोल बदल जायेगा। □□

भारत की ताकत और विपक्ष की राजनीति का नया द्वाद

ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का एक सशक्त प्रतीक बन चुका है। इस ऑपरेशन ने न केवल सीमाओं पर बैठे दुश्मनों को सीधा संदेश दिया है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी भारत की स्थिति को मजबूत किया है। देशभर में इस ऑपरेशन की सराहना हो रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से लेकर कई बड़े देशों ने भारत के इस साहसी कदम की प्रशंसा की है। लेकिन देश के भीतर एक अजीब सा राजनीतिक संघर्ष भी शुरू हो गया है। जिस समय जनता एकजुट होकर सेना के पराक्रम पर गर्व कर रही है, उसी समय प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस इस ऑपरेशन पर सवाल उठाकर खुद को कठघरे में खड़ा कर रही है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जिस तरह सरकार से यह पूछा कि कितने फाइटर प्लेन गिरे, यह सवाल वाजिब होते हुए भी एक गलत समय पर उठाया गया। जब देश युद्ध की स्थिति में होता है, तब जवाबदेही का मतलब समर्थन होता है, न कि सवालों की बौछार। राहुल गांधी का यह बयान कि "सच जानना हमारा हक है" अपने आप में सही है, लेकिन यह भी उतना ही जरूरी है कि सेना के मनोबल को ऐसे समय में ठेस न पहुंचे। एयर मार्शल एके भारती ने साफ कहा है कि हम युद्ध की स्थिति में हैं और इसमें नुकसान भी होता है, लेकिन क्या हमने अपने लक्ष्य हासिल किए? जवाब है हां। तो जब सेना खुद कह रही है कि उन्होंने मिशन को सफलता से पूरा किया है, तो सवाल पूछने की टाइमिंग पर बहस तो होगी ही।

विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर को 'मुखबिर' कहने का आरोप और भी गंभीर है। कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और पवन खेड़ा ने यह दावा किया कि जयशंकर ने ऑपरेशन से पहले पाकिस्तान को सूचना दे दी, जिससे आतंकवादी बच निकले। इस दावे के पीछे जयशंकर का वह बयान है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत ने पाकिस्तान को स्पष्ट किया कि हमला आतंकवादियों पर होगा, न कि पाकिस्तानी सेना पर। यह बयान युद्ध को टालने और अंतरराष्ट्रीय समुदाय का समर्थन जुटाने की कूटनीतिक कोशिश थी, लेकिन विपक्ष ने इसे एक तरह से देशद्रोह करार दे दिया। क्या यह उचित है कि एक वैश्विक कूटनीति को इस तरह राजनीति का विषय बना दिया जाए?



ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का एक सशक्त प्रतीक बन चुका है।

— अजय कुमार

राहुल गांधी की यह बात कि अगर पाकिस्तान को पहले से जानकारी थी तो मसूदा अजहर के घर के दस से ज्यादा लोग मारे कैसे गए? अपने आप में कांग्रेस के आरोपों को खारिज करने के लिए काफी है। यह साफ संकेत है कि भारत ने एक तरफ आतंकियों को मार गिराया, वहीं पाकिस्तान की सेना से सीधी भिड़ंत से बचकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को मजबूत किया। इस रणनीति को कोई समझे या न समझे, पर इसे मुखबिरी कहना न केवल बचकाना है बल्कि खतरनाक भी।

इस पूरे ऑपरेशन पर जो राजनीतिक विवाद खड़ा हुआ है, वह अब बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों के आगामी विधानसभा चुनावों का मुख्य मुद्दा बनता जा रहा है। भाजपा इस ऑपरेशन को राष्ट्रवादी अभियान के रूप में पेश कर रही है, तो वहीं कांग्रेस

इसे बीजेपी द्वारा राष्ट्रवाद के नाम पर 'राजनीतिक सौदा' बता रही है। कांग्रेस द्वारा 'सिंदूर का सौदागर' जैसे शब्दों का इस्तेमाल यह बताता है कि राजनीति का स्तर किस दिशा में जा रहा है। क्या यह वही पार्टी है जिसने सर्वदलीय बैठक में सरकार को पूरा समर्थन देने का वादा किया था? 8 मई 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कहा था कि इस संकट की घड़ी में हम सरकार के साथ हैं। लेकिन ठीक एक हफ्ते बाद कांग्रेस नेताओं के सुर बदल गए। अब सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस की उस प्रतिबद्धता का क्या हुआ?

दरअसल, कांग्रेस की रणनीति अब जय हिंद सभाओं के जरिए भाजपा पर हमला करने की है। 20 से 30 मई के बीच देशभर में कांग्रेस ऐसी सभाएं आयोजित कर रही है जिसमें यह बताया जाएगा कि कैसे बीजेपी राष्ट्रीय सुरक्षा का राजनीतिकरण कर रही है। लेकिन जनता यह सवाल भी पूछ रही है कि क्या यह सभाएं सेना के मनोबल के खिलाफ नहीं जा रही हैं? क्या इन सभाओं का मकसद राष्ट्रवाद की भावना को चोट पहुंचाना नहीं है?

भारत में विपक्ष की भूमिका बहुत अहम होती है। लोकतंत्र में यह विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि वह सरकार को जवाबदेह बनाए, गलतियों की ओर ध्यान दिलाए। लेकिन जब देश युद्ध की स्थिति में होता है, तब आलोचना और समर्थन के बीच की रेखा बहुत महीन हो जाती है। यही वजह है कि 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 की बालाकोट एयरस्ट्राइक के समय कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने आरंभिक रूप से सरकार का समर्थन किया था, लेकिन जैसे ही चुनावी राजनीति आई, उन्होंने मोर्चा बदल लिया। इस बार भी कुछ वैसा ही हो रहा है।



राहुल गांधी द्वारा उठाए गए सवालों में यह भी शामिल था कि भारत के कितने फाइटर प्लेन गिरे। तकनीकी रूप से देखा जाए तो यह सवाल उचित हो सकता है, लेकिन इस सवाल का समय और मंच गलत है। युद्ध के समय इस तरह के सवालों से दुश्मन देश को ही लाभ होता है। पाकिस्तान की संसद में बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत ने रात के अंधेरे में हमला किया और इसे कायरता करार दिया। जब पाकिस्तान की सरकार भारत को कायर बता रही है और भारत का विपक्ष कह रहा है कि भारत ने हमला बताकर किया, तो क्या इससे भारत की छवि को नुकसान नहीं होता?

सेना के लिए सबसे बड़ा हथियार होता है जनता का समर्थन। अगर देश की जनता एकजुट होकर अपने जवानों के पीछे खड़ी हो तो सेना का मनोबल ऊँचा रहता है। लेकिन जब देश के भीतर से ही विपक्ष इस तरह के सवाल उठाकर सेना की नीतियों पर संदेह करता है, तो यह सवाल जरूर उठता है कि क्या यह आलोचना है या राजनीतिक हथियार?

कांग्रेस नेताओं ने जिस तरह सिंदूर का सौदागर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है, वह भारतीय राजनीति की भाषा के स्तर को गिराता है। यह वही कांग्रेस है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कभी मौत का सौदागर कहा था। अब सिंदूर का सौदागर कहकर बीजेपी को यह

जताया जा रहा है कि वह देशभक्ति को बेचना चाहती है। लेकिन सवाल यह है कि अगर बीजेपी राष्ट्रवाद को बेच रही है, तो उसे खरीद कौन रहा है? क्या जनता इतनी भोली है कि वह राष्ट्रवाद के नाम पर सब कुछ भूल जाती है?

आज जब ऑपरेशन सिंदूर जैसे सैन्य अभियानों के जरिए भारत अपनी सीमाओं को सुरक्षित कर रहा है, आतंकवाद के खिलाफ खुलकर मोर्चा ले रहा है, तो क्या विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वह इन प्रयासों का समर्थन करें? आलोचना जरूर होनी चाहिए लेकिन समय देखकर, मंच देखकर और शब्दों को मापकर। आज भारत का आम नागरिक यह पूछ रहा है कि जब देश युद्ध के मुहाने पर खड़ा हो, तब विपक्ष क्यों एकजुट नहीं हो सकता? क्या राजनीति इतनी जरूरी हो गई है कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा से भी ऊपर हो जाए?

भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहां सवाल पूछने की आजादी सबको है। लेकिन सवाल वही पूछे जाते हैं जो जरूरी हों, और समय वही चुना जाता है जो उचित हो। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस की बदली हुई रणनीति और तीखे आरोप न केवल उसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रहे हैं, बल्कि देश की एकता और अखंडता के लिए भी खतरे की घंटी हैं। जनता सब देख रही है, और आने वाले चुनावों में इसका जवाब जरूर देगी। □□

रक्षा क्षेत्र में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता

‘ऑपरेशन सिंदूर’ भारतीय सैन्य इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय है, जिसने न केवल भारतीय सेना की रणनीतिक क्षमता को दर्शाया, बल्कि ‘मेक इन इंडिया’ पहल के तहत स्वदेशी सैन्य साजो-सामान की प्रभावशीलता को भी प्रमाणित किया। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई ‘मेक इन इंडिया’ योजना का उद्देश्य देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उपयोग में आए स्वदेशी हथियारों, ड्रोन, संचार उपकरणों ने यह साबित किया कि भारत अब विदेशी उपकरणों पर निर्भर नहीं रहना चाहता, बल्कि आत्मनिर्भर और स्वावलंबी रक्षा शक्ति बनने की दिशा में अग्रसर है। चाहे ड्रोन युद्ध हो, मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस हो या इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, ‘ऑपरेशन सिंदूर’ सैन्य अभियानों में तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की यात्रा में एक मील का पत्थर साबित हुआ है।

ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि

ऑपरेशन सिंदूर, एक सामरिक रूप से संवेदनशील और रणनीतिक अभियान था, जिसका लक्ष्य पाकिस्तान स्थित आंतकी शिविरों और दुश्मन की गतिविधियों पर निर्णायक प्रहार करना था। यह अभियान जटिल परिस्थितियों और उच्च जोखिम वाले इलाकों में संचालित किया गया। ऐसी परिस्थितियों में सैनिकों को उन्नत, विश्वसनीय और परिस्थितियों के अनुसार अनुकूल सैन्य साजो-सामान की आवश्यकता होती है। यहीं पर ‘मेक इन इंडिया’ के तहत विकसित उपकरणों ने अपनी उपयोगिता सिद्ध की हैं।

भारत की वायु रक्षा प्रणाली ने सेना, नौसेना और मुख्य रूप से वायु सेना की रक्षा प्रणालियों को मिलाकर असाधारण तालमेल के साथ काम किया। इन प्रणालियों ने एक अभेद्य दीवार बनाई, जिसने पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के प्रयासों को विफल कर दिया। भारतीय वायु सेना की एकीकृत वायु कमान एवं नियंत्रण प्रणाली (आई.ए.सी.सी.एस.) ने सभी संसाधनों को एक साथ लाकर आधुनिक युद्ध के लिए महत्वपूर्ण नेटवर्क केन्द्रित परिचालन क्षमता प्रदान की।

मेक इन इंडिया सैनिक साजो-सामान की प्रमुख भूमिकाएं:

1. **स्वदेशी हथियार प्रणाली:** ‘मेक इन इंडिया’ के तहत पिनाका (मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर), धनुष (तोप), और ब्रह्मोस (मिसाइल सिस्टम) जैसी स्वदेशी हथियार प्रणालियाँ निर्णायक साबित हुईं। ये सभी हथियार रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) और भारत फोर्ज, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड आदि भारतीय संस्थानों द्वारा निर्मित हैं। इनके उपयोग से भारत ने यह दिखाया कि वह आधुनिक तकनीक से लैस युद्ध उपकरणों का निर्माण स्वयं कर सकता है।

2. **ड्रोन और निगरानी प्रणाली:** ‘मेक इन इंडिया’ के अंतर्गत भारत ने ड्रोन तकनीक में काफी प्रगति की है। स्वदेशी ड्रोन ‘स्विच’, ‘नाग’ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से लैस यूएवी और लो-एल्टिट्यूड निगरानी ड्रोन का उपयोग किया गया। इनसे दुश्मन की गतिविधियों की निगरानी करना, लक्ष्यों की पहचान और सटीक हमला संभव हुआ। यह रणनीतिक बढ़त का बड़ा कारण बना। आकाशतीर प्रणाली ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के वायु रक्षा



ऑपरेशन सिंदूर ने ‘मेक इन इंडिया’ के तहत विकसित सैन्य साजो-सामान की उपयोगिता और विश्वसनीयता को सिद्ध कर दिया है। इस अभियान ने न केवल भारत की सैन्य क्षमता को सशक्त किया, बल्कि यह भी स्पष्ट कर दिया कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है।

— दुलीचंद कालीरमन

नेटवर्क का एक हिस्सा थी, इस प्रणाली ने पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल हमलों को प्रभावी ढंग से विफल कर दिया था।

3. संचार और नियंत्रण प्रणाली: किसी भी सैन्य अभियान के दौरान सैनिकों और कमांड सेंटर के बीच निर्बाध और सुरक्षित संचार अत्यंत आवश्यक होता है। इसके लिए सामरिक संचार प्रणाली (टीसीएस) जैसे स्वदेशी रूप से विकसित संचार नेटवर्क सुरक्षित और गोपनीय संचार सुनिश्चित करता है। इस प्रणाली से सभी सैन्य इकाइयों को आपस में जोड़ने में अहम भूमिका होती है।

4. बख्तरबंद वाहन और परिवहन: आज भारतीय सैन्य बल 'अर्जुन टैंक', टाटा केस्ट्रेल आर्मर्ड व्हीकल, और एल एण्ड टी द्वारा निर्मित इंफैंट्री फाइटिंग व्हीकल्स का प्रभावी उपयोग कर रहे हैं। इन सभी वाहनों की विशेषता यह है कि ये कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में भी कुशलता से काम करते हैं। भारतीय सेना ने अपने इन स्वदेशी संसाधनों के माध्यम से दुर्गम इलाकों में तेजी से पहुंच बनाने और सुरक्षा बनाए रखने में सफलता प्राप्त की है।

'मेक इन इंडिया' से आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम

'मेक इन इंडिया' पहल के तहत निर्मित इन सैन्य उपकरणों ने न केवल भारत की सैन्य ताकत को बढ़ाया, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्वायत्तता और आत्मनिर्भरता की छवि को भी मजबूत किया। ऑपरेशन सिंदूर में इनका उपयोग यह दर्शाता है कि भारत अब आयातित हथियारों पर निर्भर नहीं है, बल्कि युद्धकालीन आवश्यकताओं के अनुसार त्वरित रूप से उपकरणों का निर्माण और प्रयोग कर सकता है। इसके अतिरिक्त स्वदेशी रक्षा उत्पादन से विदेशी मुद्रा की बचत, स्थानीय रोजगार में वृद्धि, तकनीकी आत्मनिर्भरता का विकास,

रक्षा क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहन को भी बढ़ावा मिला है।

रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की भूमिका

'मेक इन इंडिया' की सफलता में निजी क्षेत्र का योगदान भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। कई कंपनियों जैसे एल एण्ड टी टाटा डिफेंस, भारत फोर्ज, और महिंद्रा डिफेंस ने रक्षा उत्पादन में नवाचार और दक्षता को बढ़ाया है। उनके द्वारा बनाए गए उपकरण न केवल गुणवत्ता में विदेशी उपकरणों के समकक्ष हैं, बल्कि लागत और रणनीतिक क्षमता के लिहाज से भी लाभकारी हैं।

रक्षा निर्यात में नया कीर्तिमान

स्वदेशी रक्षा उत्पादन ने न केवल घरेलू जरूरतों को पूरा किया अपितु वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत के रक्षा निर्यात ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस अवधि में रक्षा निर्यात 23,622 करोड़ रु. (लगभग 2.76 बिलियन डालर) तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12.04 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इसमें 2013-14 के 686 करोड़ रुपये के मुकाबले, 2024-25 में रक्षा निर्यात में 34 गुना वृद्धि हुई है।

वर्ष 2024-25 में निजी क्षेत्र ने 15,233 करोड़ रुपये और सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा कंपनियों (डीपीएसयू) ने 8,389 करोड़ रुपये का योगदान दिया। विशेष रूप से, डीपीएसयू के निर्यात में 42.85 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। भारत सरकार द्वारा रक्षा क्षेत्र में उत्पादन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1,762 निर्यात लाइसेंस जारी किए गए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 16.92 प्रतिशत अधिक है। साथ ही, निर्यातकों की संख्या में 17.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

भविष्य की दिशा

भारत सरकार ने उन्नत मध्यम

लड़ाकू विमान (एएमसीए) के निर्माण को भी हरी झंडी दे दी है जो भारत का एक स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ मल्टीरोल फाइटर जेट प्रोजेक्ट है, जिसे वैमानिकी विकास एजेंसी (एडीए) और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा है जो नए भारत की सामरिक ताकत का प्रतीक होगा। इसका उद्देश्य भारतीय वायुसेना को एक अत्याधुनिक, आत्मनिर्भर और वैश्विक मानकों वाला लड़ाकू विमान प्रदान करना है, जो रूस के एसयू-57, अमेरिका के एफ-22 रैप्टर और चीन के जे-20 जैसे विमानों की टक्कर में हो। फाइटर जेट तेजस के लिए कावेरी इंजन के भी प्रायोगिक चरण से आगे बढ़ने की सम्भावना है जिससे भारत का अपना फाइटर जेट इंजन हो ताकि वायुसेना के लिए स्वदेशी फाइटर जेट 'तेजस' की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

निष्कर्ष

ऑपरेशन सिंदूर ने 'मेक इन इंडिया' के तहत विकसित सैन्य साजो-सामान की उपयोगिता और विश्वसनीयता को सिद्ध कर दिया। इस अभियान ने न केवल भारत की सैन्य क्षमता को सशक्त किया, बल्कि यह भी स्पष्ट कर दिया कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारतीय सैनिकों को जब स्वदेशी हथियारों और तकनीक से लैस किया जाता है, तो वे अधिक आत्मविश्वास, सामर्थ्य और रणनीतिक बढ़त के साथ कार्य करते हैं। इसके अलावा भविष्य में भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर डिफेंस, उच्च गति मिसाइल तकनीक, स्वचालित और मानव रहित हथियार प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियाँ आदि क्षेत्रों में और प्रगति करनी होगी। □□

स्वदेशी का बल

भारतीय सेना के हाल के पाकिस्तान युद्ध (सर्जिकल स्ट्राइक) पराक्रम से सभी भारतीय प्रभावित हैं। सेना को और एक-दो दिन मिलते तो शायद पाकिस्तान की भारत में आतंक फैलाने की मंशा सदा के लिए खत्म हो जाती। लेकिन ठीक है राजनीति भी अपनी जगह होती है। वैसे भी ज्यादा दिन का युद्ध आजकल काम नहीं आता। यूक्रेन-रशिया और इजरायल-हमास युद्ध हम देख रहे हैं। वैसे इस युद्ध में भारतीय सेना के पराक्रम में स्वदेशी का बल दिखाई दिया। जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ 'तब' सेना की जरूरत ही नहीं है जैसी बातें होने लगी थी और तभी पाकिस्तान से युद्ध हुआ। फिर भी सेना का महत्व नहीं समझा गया। लेकिन 1962 के चीन के साथ युद्ध ने सभी की आंखें खोल दी। सेना के महत्व को समझा गया और सेना के पराक्रम का सिलसिला शुरू हुआ। यह भी सही है कि सेना को स्वदेशी का हाथ गत 10 वर्षों से मिल रहा है। और सेना का यही स्वदेशी बल वर्तमान के युद्ध में दिखाई दिया। यही स्वदेशी का बल हर क्षेत्र में दिखाना होगा तभी भारतीय जीवन आत्मनिर्भर और समृद्ध होगा।

क्या है यह स्वदेशी

स्वदेशी केवल एक आर्थिक अवधारणा नहीं है, बल्कि यह आत्मनिर्भरता, सांस्कृतिक आत्म-सम्मान और सामाजिक न्याय का प्रतीक भी है। भारत में स्वदेशी आंदोलन की जड़ें औपनिवेशिक काल से हैं जब विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और खादी जैसे स्वदेशी उत्पादों के उपयोग का आह्वान किया था। पं. दीनदयाल जी उपाध्याय के अनुसार, स्वदेशी का तात्पर्य केवल "देश में बना हुआ" नहीं है, बल्कि इसका गहरा संबंध देश की आवश्यकताओं, स्थानीय संसाधनों, समाज की सांस्कृतिक चेतना तथा आत्मनिर्भरता की भावना से है। कोई भी विचार, नीति या वस्तु एवं सेवा भारतीय समाज की प्रकृति, परंपरा, भूगोल, संसाधन और संस्कृति के अनुकूल हो तो उसे स्वदेशी कहा जा सकता है। पंडित उपाध्याय जी मानते थे कि भारतीय संस्कृति का आधार "धर्म" है, न कि केवल अर्थ। अतः कोई भी आर्थिक मॉडल



स्वदेशी केवल एक
आर्थिक अवधारणा नहीं
है, बल्कि यह
आत्मनिर्भरता, सांस्कृतिक
आत्म-सम्मान और
सामाजिक न्याय का
प्रतीक भी है।
— अनिल जवलेकर



तभी स्वीकार्य है जब वह संस्कृति और धर्म—संवेदनाओं के अनुकूल हो। स्वदेशी का आधार स्थानीय संसाधनों और स्थानीय कौशल का प्रयोग तो है ही लेकिन यह भी आवश्यक है कि उत्पादन और वितरण का ढांचा विकेंद्रित और समाज—केंद्रित होना चाहिए, न कि केवल पूंजी—केंद्रित या राज्य—केंद्रित। पंडित उपाध्याय जी के अनुसार, “जिस वस्तु का उत्पादन समाज के हित में न हो, वह भले ही देश में बनी हो, स्वदेशी नहीं कही जा सकती।” इसलिए स्वदेशी न केवल आर्थिक स्वतंत्रता की बात करता है, बल्कि मानसिक और बौद्धिक गुलामी से मुक्ति की भी प्रेरणा देता है। जब देशवासी अपने संसाधनों, ज्ञान और परंपराओं में विश्वास रखते हैं, तभी वास्तविक आत्मनिर्भरता आती है। वर्तमान भारत में, वैश्वीकरण के व्यापक प्रभाव के बीच स्वदेशी की प्रासंगिकता फिर से केंद्र में आ गई है। पाकिस्तान से युद्ध ने तो इसे आवश्यक ही करार दिया है। और अब भारत में स्वदेशी की स्थिति धीरे-धीरे सशक्त हो रही है, यह गर्व की बात है।

देश में स्वदेशी की स्थिति

भारत में स्वदेशी की स्थिति एक जटिल लेकिन महत्वपूर्ण विषय है, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से लगातार विकसित हो रही है। व्यावहारिक तौर पर स्वदेशी का आशय है — देश में निर्मित वस्तुओं, सेवाओं और तकनीकों को प्राथमिकता देना, जिससे आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिले। भारत की अर्थव्यवस्था में स्वदेशी उत्पादों का योगदान धीरे-धीरे बढ़ रहा है, विशेष रूप से एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) क्षेत्र, कृषि आधारित उद्योग, और स्वदेशी स्टार्टअप के माध्यम से। सरकार की मेक-इन इंडिया पहल ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने का प्रयास किया है और

पीएलआई (उत्पादन आधारित प्रोत्साहन) योजनाओं से मोबाइल निर्माण, फार्मा और टेक उद्योग में कुछ सकारात्मक परिणाम देखने को भी मिले हैं। इसके बावजूद, भारत अभी भी उच्च तकनीकी उत्पादों और आपूर्ति शृंखलाओं में बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है। वैसे सरकार ने ‘वोकल फॉर लोकल’, ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’, ‘एक जिला, एक उत्पाद’ (ओडीओपी) जैसी योजनाओं को लागू किया है, जिससे स्थानीय उत्पादन और रोजगार को बढ़ावा मिल सके। इसके अलावा, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया जैसी पहलें भी स्वदेशी को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन देती हैं। हालांकि, कई योजनाएं जमीनी स्तर पर धीमी प्रगति से जूझ रही हैं। ब्यूरोक्रेटिक बाधाएं, वित्तीय संसाधनों की सीमाएं और तकनीकी क्षमता की कमी एक बड़ी चुनौती बनी हुई हैं। यह सही है कि स्वदेशी तकनीकी विकास में गत कुछ वर्षों से उल्लेखनीय प्रगति हो रही है। डीआरडीओ, इसरो जैसे संस्थानों ने रक्षा और अंतरिक्ष में स्वदेशी क्षमताएं सिद्ध की हैं और स्टार्टअप क्षेत्र में जरोधा, पेटीएम, ओला, मेपमाईइंडिया जैसे स्वदेशी समाधान विकसित हुए हैं। फिर भी, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में भारत को अभी लंबा रास्ता तय करना है।

सरकार सब कुछ नहीं कर सकती

यह विदित है कि भारतीय समाज का एक वर्ग स्वदेशी वस्तुओं को गर्व और सांस्कृतिक पहचान से जोड़ता है तो दूसरी तरफ शहरी मध्यवर्ग और उच्चवर्ग के लिए आज भी विदेशी ब्रांड एक “प्रतिष्ठा प्रतीक” बने हुए हैं जिससे स्वदेशी उत्पादों को विपणन और ब्रांडिंग के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। इसलिए सरकार सब कुछ करेगी यह मानना गलत होगा। सभी

भारतीय को स्वदेशी आंदोलन से जुड़ना होगा और स्वदेशी को बल देना होगा। सरकार और उद्यमी को भी गुणवत्ता और नवाचार को स्वीकार करना होगा तथा छोटे उद्यमों को ऋण, प्रशिक्षण, और तकनीकी सहायता की व्यवस्था करनी होगी। स्वदेशी उत्पादों की ब्रांड पहचान भी जरूरी रहेगी।

स्वदेशी नीति ही राष्ट्र का बल

भारतीय विचार एकात्म मानव दर्शन में स्वदेशी एक जीवन पद्धति मानी गई है जो व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और प्रकृति के बीच संतुलन और समरसता स्थापित करती है। यह दृष्टिकोण उपभोग और विकास के बजाय कर्तव्य, संतुलन, और आत्मिक उन्नति को महत्व देता है। स्वदेशी न केवल आत्मनिर्भरता की दिशा में एक कदम है, बल्कि यह एक राष्ट्रीय पुनर्जागरण का आधार है। आज के वैश्वीकरण और भौतिकवाद के दौर में, यह स्वदेशी अवधारणा ही भारतीय नीति में उपयोगी होगी।

स्वदेशी आंदोलन सशक्त करना होगा

भारत के पास अवसर हैं लेकिन उसके लिए स्वदेशी जरूरी है। भारत के पास एक विशाल घरेलू बाजार है जो स्वदेशी उत्पादों की स्थिर मांग बन सकता है। सरकार और निजी क्षेत्र के सहयोग से स्वदेशी उद्योगों को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया जा सकता है और उसके लिए नवाचार और उद्यमशील युवा को बल और साथ मिलना जरूरी है। आवश्यक है कि नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन, तकनीकी नवाचार में निवेश, और सामाजिक मानसिकता में बदलाव लाकर स्वदेशी को एक सशक्त और प्रतिस्पर्धी विकल्प बनाया जाए। यदि भारत “ग्लोबल इन वीज़न, लोकल इन प्रैक्टिस” की नीति अपनाए, तो स्वदेशी आंदोलन 21वीं सदी में भारत को वैश्विक नेतृत्व की दिशा में अग्रसर कर सकता है। □□

नरेंद्र मोदी सरकार के सुशासन के सफल 11 साल

साकार हो रहा सामाजिक न्याय का सपना

केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के आज 11 साल पूरे हो रहे हैं। विगत ग्यारह वर्षों का यदि ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जनकल्याणकारी योजनाओं के जरिये वंचित वर्ग की अस्मिता और स्वाभिमान को सुदृढ़ किया है। पिछड़ा, दलित और आदिवासी अस्मिता की इस नीति का ध्येय वाक्य है 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास'।

आज ग्यारह वर्षों के सुशासन के बाद यह कहा जा सकता है कि संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर ने जिस भारत का सपना देखा था, उसे केंद्र की राजग सरकार पूरा कर रही है। जातिगत जनगणना का निर्णय पिछड़ा, दलित और आदिवासियों के अधिकार और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जाति जनगणना की तारीखों का ऐलान करके सरकार ने यह संदेह दूर कर दिया है कि वह इस मुद्दे पर सुस्ती बरतना चाहती है। तय कार्यक्रम के अनुसार 1 मार्च 2027 की आधी रात को जनगणना खत्म हो जाएगी। अब अगला सवाल है कि इसके आंकड़े कितनी जल्दी सार्वजनिक होते हैं यह सवाल खास और अहम है। वजह यह है कि इस बार इन आंकड़ों से लोकसभा चुनाव क्षेत्र के परिसीमन और महिला आरक्षण का मामला भी जुड़ा हुआ है। ज्ञात हो कि आजाद भारत में जातियों पर बहुत राजनीति हुई लेकिन कभी उसका हिसाब नहीं रखा गया। ऐसे में यह जातिगत जनगणना पूरे परिदृश्य को बदल कर रख देगी। इसका पहला असर होगा लोकसभा सीटों की संख्या पर, जिस पर कोई फैसला पांच दशकों से टलता आ रहा है। देश की बढ़ती आबादी को अब संसद में अपने ज्यादा प्रतिनिधि चाहिए, क्योंकि जितने अधिक प्रतिनिधि होंगे जनता के हित की बात भी उसी संख्या में बढ़ेगी। वर्ष 1976 में इंदिरा गांधी ने और वर्ष 2001 में अटल बिहारी वाजपेई की सरकारों ने परिसीमन कराया था, लेकिन सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई गई। इंदिरा गांधी सरकार ने 25 साल के लिए सीटें बढ़ाने पर रोक लगा दी थी फिर वाजपेई सरकार ने भी इस प्रक्रिया को बरकरार रखा था। वर्ष 2026 में यह मियाद खत्म हो रही है, यानी अब जो जनगणना होने जा रही है उसी के आधार पर सरकार को परिसीमन



आज ग्यारह वर्षों के सुशासन के बाद यह कहा जा सकता है कि संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर ने जिस भारत का सपना देखा था, उसे केंद्र की राजग सरकार पूरा कर रही है।

— डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्र



से जुड़ा अहम फैसला भी लेना है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जाति जनगणना के साथ एक और महत्वपूर्ण मुद्दा जुड़ा हुआ है और वह मामला है आरक्षण का। जनगणना के आंकड़े आने के बाद उन नए आंकड़ों के आधार पर आरक्षण में बदलाव की मांग भी तेजी से होगी। हालांकि आरक्षण की सीमा को लेकर कई तरह की राजनीतिक और कानूनी पेंच भी हैं जिसे ठीक से सुलझाए बिना सही दिशा में आगे बढ़ना थोड़ा कठिन काम होगा लेकिन केंद्र की मोदी सरकार जिस प्रकार हर मुद्दे पर आम सहमति कायम करते हुए रास्ता निकालने में सफल रही है लोगों को उम्मीद है कि यह मामला भी समय के साथ सुलझेगा और सबके बेहतर विकास के रास्ते खुलेंगे भारत 2047 तक एक अति विकसित भारत के रूप में प्रतिष्ठित होगा।

पिछले 11 वर्षों में, मुख्य रूप से उपेक्षित और ग्रामीण पृष्ठभूमि से 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूहों में शामिल हुई हैं। लखपति दीदी कार्यक्रम की शुरुआत से लेकर अब तक 1.25 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है और आर्थिक कार्यक्रमों के माध्यम से तीन करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। नमो ड्रोन दीदी के नाम से जानी जाने वाली ड्रोन चलाने वाली महिलाओं ने महिलाओं के बारे में समुदाय की धारणा बदल दी है।

मोदी सरकार के स्टैंडअप इंडिया योजना के तहत बैंक की प्रत्येक ब्रांच अपने क्षेत्र के एक दलित, एक महिला और एक आदिवासी को लोन देगी। इसके तहत 2.5 लाख दलित उद्यमी तैयार करने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि सामाजिक न्याय हमारी सरकार के लिए सिर्फ कहने-सुनने की बात नहीं, बल्कि एक कमिटमेंट है, हमारी श्रद्धा है। इसी को पूरा करते हुए उन्होंने

जहां तक भारतीय आर्थिकी का सवाल है तो भारत का आर्थिक विकास उत्साहजनक है। आज जब दुनिया के दूसरे इमर्जिंग देश मुश्किल में फंसे हैं भारत की अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है।

2020 के 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में एससी/एसटी और अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है।

2014 में आरंभ किए गए प्रधानमंत्री वनबंधु कल्याण योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए। इसके तहत जनजातीय आबादी की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को सुधारते हुए उनके सशक्तिकरण के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, बुनियादी ढांचे और संचार समेत 14 क्षेत्र निर्धारित किए गए। अनुसूचित जनजाति के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय योजना की स्थापना की गई है। वर्ष 2026 तक देश भर में 728 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्थापित करने का लक्ष्य है।

2025-26 के बजट में प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना का विस्तार करते हुए इसे धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अन्तर्गत शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार में बुनियादी ढांचे की कमी को पूरा करना है। मोदी सरकार ने बाबा साहब से जुड़े पंचतीर्थों-जन्मस्थान महु, दीक्षा स्थल नागपुर,

चैतन्य भूमि भूमि इंदु मिल मुंबई, शिक्षा भूमि लंदन और महापरिनिर्वाण स्थल दिल्ली में स्मारकों के निर्माण व जीर्णोद्धार की पहल की। बाबा साहब को भारत रत्न भी तब दिया गया, जब केंद्र में बीजेपी समर्थित वी.पी. सिंह की सरकार थी। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू न सिर्फ अनुसूचित जनजाति वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रही हैं बल्कि सबकी साझेदारी, सबकी भागीदारी, सबकी हिस्सेदारी नीति को भी प्रतिबिंबित भी कर रही हैं।

जहां तक भारतीय आर्थिकी का सवाल है तो भारत का आर्थिक विकास उत्साहजनक है। आज जब दुनिया के दूसरे इमर्जिंग देश मुश्किल में फंसे हैं भारत की अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है। वित्त वर्ष 2025 में सकल घरेलू उत्पाद ग्रोथ को संशोधित कर 6.3 प्रतिशत से 6.5 प्रतिशत किया गया है। पहली नजर में हम इसे अच्छा कह सकते हैं लेकिन बहुत उत्साह जनक तो नहीं कह सकते लेकिन वित्त वर्ष 2024 में भी सकल घरेलू उत्पाद ग्रोथ को संशोधित कर 8.5 02 से 9.2 प्रतिशत किया गया था, हमें इस अनुमान को उसी के संदर्भ में समझने का आधार बनाना होगा। दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों का मानना है कि वैश्विक ग्रोथ घटेगा लेकिन भारत की ग्रोथ न सिर्फ स्थिर रहेगी बल्कि धीरे-धीरे आगे की ओर बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में चिन्हित होगी। भारत की मैक्रो इकोनॉमी अच्छी लग रही है क्योंकि राजकोषीय और व्यापार घाटा इस समय नियंत्रण में है। महंगाई दर पर सरकार का काबू है। हालांकि खराब शिक्षा व्यवस्था और पुलिस तथा न्याय प्रणाली की चुनौतियां अब भी बरकरार हैं लेकिन इसके बावजूद भारत आने वाले वक्त में 7 प्रतिशत से अधिक का विकास दर हासिल करने की ओर बढ़ रहा है, और यह सब पिछले 11 साल से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की राजग सरकार प्रयासों का नतीजा है। □□

कश्मीर की पुकार

कश्मीर के लोग उतने ही मधुर हैं जितने वहां के सेब। जब आप कश्मीर जाएंगे, तब इसे स्वयं अनुभव कर पाएंगे। प्रकृति ने कश्मीर पर अनमोल खजाने लुटाकर इसे अद्वितीय सौंदर्य से संवारा है। यही वजह है कि कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। एक ऐसा स्वर्ग जहां मधुर फल और मधुर लोग मिलकर इसे पूर्णता देते हैं।

प्राकृतिक सौंदर्य के कारण कश्मीर में खेती के साथ-साथ पर्यटन भी आजीविका का प्रमुख स्रोत है। पहाड़ों और जंगलों के बीच जो थोड़ी-बहुत जमीन है, उसी पर लोग खेती करते हैं। साथ ही लकड़ी की वस्तुएं बनाते हैं, भेड़-बकरियां पालते हैं। यहां के मेहनती लोग सीमित संसाधनों और सीमित आय के बावजूद संतोष के साथ सादगी भरा जीवन जीना जानते हैं।

पिछले कई दशकों से कश्मीर घाटी एक विवादित क्षेत्र बना हुआ है, जो तीन हिस्सों में बंटा है। वर्तमान में इसका लगभग 45.62 प्रतिशत हिस्सा भारत के नियंत्रण में, 35.15 प्रतिशत पाकिस्तान के नियंत्रण में और 19.23 प्रतिशत चीन के अधीन है। वर्तमान केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का कुल क्षेत्रफल लगभग 42,241 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें कश्मीर घाटी का क्षेत्रफल लगभग 15,948 वर्ग किलोमीटर है।

कश्मीर की 2025 की अनुमानित जनसंख्या लगभग 80 लाख है, यानी करीब 16 लाख परिवार। खेती योग्य भूमि मात्र 3.38 लाख हेक्टेयर है। प्रति परिवार औसतन 0.21 हेक्टेयर (लगभग 2 कनाल) और प्रति व्यक्ति केवल 0.04 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध है, जिससे उनकी जीविका की सीमाएं स्पष्ट होती हैं।

कश्मीर में सेब, अखरोट, बादाम, खुबानी, चेरी जैसे फल, और चावल, मक्का, दालें, सरसों जैसी फसलें उगाई जाती हैं। 'सेब का कटोरा' कहे जाने वाले इस क्षेत्र में लगभग आधी खेती योग्य भूमि यानी 1.62 लाख हेक्टेयर पर सेब की खेती होती है और भारत का 75 प्रतिशत सेब 20 लाख टन उगाया जाता है। इसके अलावा केसर, शहद, मशरूम और वनों पर आधारित लकड़ी, हस्तशिल्प, क्रिकेट बैट और जड़ी-बूटियों का उत्पादन होता है। यह क्षेत्र पश्मीना शॉल और कालीनों के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है।

सरकारी नीतियों ने पूरे देश में खेती और उससे जुड़े रोजगार को घाटे का सौदा बना



संवाद, सम्मान और न्याय ही वह रास्ता है जिससे कश्मीर को न केवल सुरक्षित, बल्कि समृद्ध और सच्चे अर्थों में 'धरती का स्वर्ग' बनाया जा सकता है।
— विवेकानंद माथने



दिया है। कश्मीर भी इससे अछूता नहीं है। बल्कि यहां प्रति व्यक्ति कृषि भूमि अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और भी कठिन हो जाती है।

पर्यटन कश्मीर में रोजगार का एक प्रमुख स्रोत है। पर्यटकों के लिए आवास, भोजन, परिवहन और सांस्कृतिक गतिविधियों से लोगों को रोजगार मिलता है। प्राकृतिक दृष्टि से अनुकूल मौसम में लगभग 7-8 महीने पर्यटन से अच्छा खासा रोजगार सृजित होता है। यह रोजगार पूरी तरह मौसम, पर्यावरणीय परिस्थितियों और कानून-व्यवस्था की स्थिरता पर निर्भर करता है।

कश्मीर आर्थिक दृष्टि से एक मध्यम आय वाला प्रदेश है। रोजगार के साधन सीमित हैं। प्रति व्यक्ति वार्षिक आय राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में इसकी रैंकिंग 25 से 28वें स्थान के बीच आती है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि खेती और पर्यटन कश्मीरी लोगों की आजीविका की जीवन रेखा है। जब पर्यटन प्रभावित होता है, तो उनकी जीवन रेखा भी मानो बर्फ की तरह जम जाती है।

ऐसे में यह सहज समझदारी है कि कोई भी समाज आतंकवाद का समर्थन करके अपने जीवन को संकट में नहीं डालना चाहेगा। कश्मीरी जनता की प्राथमिकता भी शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखना और पर्यटन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाए रखना ही रही है।

दुर्भाग्य से पूरे कश्मीर को आतंकवाद से जोड़कर देखा जाने लगा है। पूरे देश में यह दुष्प्रचार फैलाया जाता है कि वहां आतंकवादी पलते और बढ़ते हैं। कुछ मीडिया संस्थान इस दुष्प्रचार को व्यवसाय बना चुके हैं। इसकी सबसे बड़ी कीमत कश्मीर की जनता को चुकानी पड़ती है क्योंकि इससे पर्यटन प्रभावित होता है और उनकी आमदनी कम हो जाती है।

ऐसा नहीं है कि कश्मीर में आतंकी गतिविधियां नहीं होतीं। हर समाज में कुछ कट्टरपंथी तत्व होते हैं, जो अपने आग्रह को समाज पर थोपते हैं और हिंसा का रास्ता अपनाते हैं। कश्मीर में भी लगभग 3-4 प्रतिशत ऐसे तत्व मौजूद हैं। लेकिन कश्मीर के 95 प्रतिशत से अधिक लोग हिंसा का समर्थन नहीं करते। उन्होंने हर चुनाव में डर की दीवारें तोड़कर और 'लोगों की सरकार' बनाने में सक्रिय भूमिका निभाकर यह साबित किया है।

कश्मीर में एक वर्ग मानता है कि वे दो देशों के सत्ता संघर्ष के बीच पिस रहे हैं। तथाकथित आधुनिक विकास के कारण तापमान वृद्धि, जलवायु परिवर्तन और अन्य पर्यावरणीय संकट गहराते जा रहे हैं। ग्लेशियरों का पिघलना, बाढ़ और प्राकृतिक आपदाएं मानव जीवन को संकट में डाल रही हैं। साथ ही, स्थानीय पारंपरिक खेती और फसलें भी प्रभावित हो रही हैं। पिछले 30 सालों में कश्मीर के ग्लेशियर 20 प्रतिशत सिकुड़ गए हैं। कश्मीर के लोग इस स्वर्ण भूमि को नुकसान पहुंचाने वाले विकास से चिंतित हैं।

अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधान हटाए जाने के बाद कश्मीरी लोगों के मन में यह डर है कि कहीं बाहरी लोगों को संपत्ति खरीदने का अधिकार देकर उनके संपत्ति अधिकार और रोजगार न छीन लिए जाएं। विकास के नाम पर पूरे देश में किसानों, आदिवासियों से उनके जल, जंगल, जमीन और खनिज आदि संसाधन छीनकर चंद उद्योगपतियों के हवाले किए जाने के आरोप सरकारों पर लगते रहे हैं। पर्यटन क्षेत्र भी बड़े उद्योग घरानों को सौंपे जाने की आशंका है।

भारत का 2025-26 का वार्षिक रक्षा बजट 6.81 लाख करोड़ रुपये है, जबकि कृषि बजट 1.27 लाख करोड़ रुपये, शिक्षा बजट 1.29 लाख करोड़ रुपये और स्वास्थ्य बजट 99.86 हजार

करोड़ रुपये है। रक्षा पर कृषि की तुलना में पांच गुना से अधिक खर्च किया जाता है। सरकार का लक्ष्य है कि 2047 तक यह रक्षा खर्च 31.7 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाया जाए। पाकिस्तान की स्थिति भी अलग नहीं है। दोनों देश सैन्य ताकत बढ़ाकर एक-दूसरे को सबक सिखाने के लिए सैन्य बजट बढ़ाते जा रहे हैं।

पाकिस्तान को यह समझना होगा कि आतंकी गतिविधियां करके निरपराध लोगों की जान लेकर आखिर वह क्या हासिल करना चाहता है? सैन्य कार्रवाई में भी दोनों तरफ के निरपराध लोग बलि चढ़ते हैं, लेकिन इससे कोई स्थायी समाधान नहीं निकलता।

कश्मीर के लोग चाहते हैं कि संवाद के माध्यम से इसका स्थायी समाधान खोजा जाना चाहिए। वे अपनी अगली पीढ़ी को, अपने निरपराध बच्चों को हिंसा का शिकार नहीं बनाना चाहते, चाहे वह किसी भी आतंकी संगठन द्वारा की गई। वे स्थायी समाधान की मांग करते हैं। कश्मीर की जनता भी शांति और अमन चाहती है।

कश्मीर केवल एक भूभाग नहीं, बल्कि वहां बसने वाले लोगों के जीवन, सपनों और संघर्षों की धरती है। यह एक ऐसा समाज है जो न्याय, शांति और सम्मान की तलाश में है। आज जरूरत इस बात की है कि हम कश्मीर को केवल सुरक्षा की नजर से न देखें, बल्कि मानवता की नजर से देखें। वहां की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जड़ों को समझें, और खेती व पर्यटन जैसे उनके पारंपरिक व्यवसायों को संरक्षण दें।

संवाद, सम्मान और न्याय ही वह रास्ता है जिससे कश्मीर को न केवल सुरक्षित, बल्कि समृद्ध और सच्चे अर्थों में 'धरती का स्वर्ग' बनाया जा सकता है। कश्मीरी लोगों के जीवन को खुशहाल, स्वतंत्र और गरिमामय बनाकर ही यह संभव है। □□

प्रधानमंत्री का स्वदेशी संदेश

आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी जरूरी

देश में इससे पहले भी कई महापुरुषों ने स्वदेशी का संदेश दिया है। स्वातंत्र्यवीर सावरकर, लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी ने तो विदेशी कपड़ों की होली भी जलाई थी। वर्ष 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ, तब लोगों के गुस्से का प्रकटीकरण स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ और अंग्रेजों को यह निर्णय वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसका प्रभाव इतना जबरदस्त था कि पूरे देश में स्वदेशी का वातावरण बन गया।

धोबी लोगों ने विदेशी कपड़े इस्त्री करने से इनकार किया, हलवाईयों ने विदेशी चीनी से मिठाई बनाना बंद किया, पुरोहितों ने विदेशी कपड़े पहनने वाले वर का विवाह कराने से मना किया, और चप्पल सुधारने वालों ने विदेशी चप्पल मरम्मत करने से इनकार कर दिया। पूरे देश ने स्वाभिमान के साथ उठ खड़ा होकर विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कर दिया। उस समय इंग्लैंड के मैनचेस्टर से मुंबई को हर साल 40,000 कपड़ों के गट्टे भेजे जाते थे, लेकिन 1905-06 में सिर्फ 40 गट्टे बिके। इससे मैनचेस्टर के व्यापारियों ने ब्रिटिश सरकार को लिखा कि यदि भारतीयों के विरोध के कारण व्यापार बंद हो रहा है, तो शासन को नीतियों पर पुनर्विचार करना होगा। और अंततः संसद द्वारा पारित बंगाल विभाजन का निर्णय रद्द कर दिया गया। यह था आर्थिक बहिष्कार का प्रभाव।

वर्तमान संदर्भ – ऑपरेशन सिंदूर और विदेशी रुख

हाल ही में हुए “ऑपरेशन सिंदूर” के समय चीन, तुर्की और अज़रबैजान ने भारत के खिलाफ बयान दिए और पाकिस्तान का समर्थन किया। चीन ने कहा कि पाकिस्तान को आत्मरक्षा का अधिकार है, और पाकिस्तान को “अच्छा मित्र” बताया। भारत पर जो ड्रोन और मिसाइल दागे गए, वे अधिकतर तुर्की और चीन में बने थे। अज़रबैजान ने भी पाकिस्तान का पक्ष लिया, जबकि भारतीय पर्यटक वहां हर साल भारी संख्या में जाते हैं। तुर्की और



हमें यह विचार करना होगा कि कौन हमारे भविष्य के सहयोगी बन सकते हैं। जो देश भारत के स्वाभिमान का सम्मान करें, उन्हीं के साथ व्यापारिक संबंध बनाए जाने चाहिए।
— अमोल पुसदकर



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में गुजरात में दिए भाषण में स्वदेशी का संदेश दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देवी-देवताओं की मूर्तियाँ तक चाइना से आ रही हैं, और हम उन्हें खरीदते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी रोजमर्रा की वस्तुओं में भारत निर्मित वस्तुओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

अज़रबैजान को भारतीय पर्यटकों से 4,700 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है।

इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में गुजरात में दिए भाषण में स्वदेशी का संदेश दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देवी-देवताओं की मूर्तियाँ तक चाइना से आ रही हैं, और हम उन्हें खरीदते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी रोजमर्रा की वस्तुओं में भारत निर्मित वस्तुओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

गुणवत्ता के नाम पर विदेशी वस्तुओं की श्रेष्ठता की मानसिकता गलत है। एक समय भारत कपड़ा भी विदेश से आयात करता था, आज भारत का कपड़ा उद्योग आत्मनिर्भर है।

भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में बहुत प्रगति की है। मंगलयान, चंद्रयान, आदित्य मिशन के जरिए भारत विश्व में अपनी पहचान बना चुका है।

पहले सिर्फ दो भारतीय मोबाइल कंपनियाँ थीं, परंतु “मेक इन इंडिया” के तहत अब एप्पल और सॅमसंग भी भारत में निर्माण कर रहे हैं। इससे प्रेरणा लेकर भारत खुद का मोबाइल भी बना सकता है। कोरोना के समय सेमीकंडक्टर चिप्स की आपूर्ति ठप होने से भारत के उद्योग प्रभावित हुए। अब भारत में ही चिप निर्माण शुरू हो चुका है।

राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वदेशी संतुलन
दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे “चाहत में स्वदेशी और मजबूरी में विदेशी”। देश की सुरक्षा हेतु यदि हमें राफेल जैसे विदेशी हथियार लेने पड़े, तो वह आवश्यक है। राफेल (फ्रांस) और एस-400 मिसाइल प्रणाली (रूस) का उपयोग “ऑपरेशन सिंदूर” में हुआ, और वह सफल भी रहा।

व्यापार घाटा और विकल्प

भारत और चीन के बीच सबसे

बड़ा व्यापार है। भारत चीन को 14 अरब डालर की वस्तुएं निर्यात करता है, लेकिन 114 अरब डालर की वस्तुएं आयात करता है। यानी भारत का व्यापार घाटा 100 अरब डालर तक पहुँच गया है।

तुर्की से 3.28 अरब डालर और अज़रबैजान से 955 मिलियन डालर की आयात होती है, जिसमें पेट्रोलियम प्रमुख है।

रूस पर जब वैश्विक प्रतिबंध लगे थे, तब भी भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा। क्योंकि यह हमारे राष्ट्रीय हित में था। पाकिस्तान का समर्थन करने वाले देशों की वस्तुओं को लोगों के घर में जगह न मिले इसके लिये पर्याप्त सामाजिक वातावरण बनाना हमारा दायित्व है।

निष्कर्ष

हमें यह विचार करना होगा कि कौन हमारे भविष्य के सहयोगी बन सकते हैं। जो देश भारत के स्वाभिमान का सम्मान करें, उन्हीं के साथ व्यापारिक संबंध बनाए जाने चाहिए।

यदि तुर्की और अज़रबैजान धर्म देखकर पाकिस्तान का समर्थन कर सकते हैं, तो हम भी “देश देखकर खरीददारी” क्यों न करें? □□

(अमोल पुसदकर, पूर्व महाराष्ट्र प्रांत संयोजक, स्वदेशी जागरण मंच, नागपुर)

:: सूचना ::

स्वदेशी पत्रिका आर्थिक सम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते हैं। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवेदना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते हैं तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।

संपादक, स्वदेशी पत्रिका

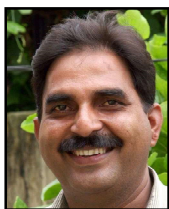
‘धर्मक्षेत्र’, सेक्टर-8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली-110022

भारत की कूटनीति का असर मॉरीशस को मिला चागोस द्वीपसमूह

चागोस द्वीपसमूह पर ब्रिटेन के 60 साल पुराने कब्जे का अंत एक ऐसे ऐतिहासिक क्षण के रूप में दर्ज हुआ है, जिसने औपनिवेशिक शासन की उन स्याह परतों को मिटा दिया है, जो आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी विश्व के कई हिस्सों पर छाई हुई थीं। 22 मई 2025 को ब्रिटेन और मॉरीशस के प्रधानमंत्रियों कीर स्टार्मर और नवीन रामगुलाम ने एक डिजिटल समारोह में उस समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे चागोस द्वीपसमूह, जिसमें डिएगो गार्सिया जैसे रणनीतिक और सैन्य दृष्टिकोण से अहम ठिकाने शामिल हैं, आधिकारिक तौर पर मॉरीशस को सौंप दिए गए। इस सौदे के पीछे एक और नाम बिना किसी शोरगुल के खड़ा रहा भारत। खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका इस पूरे कूटनीतिक घटनाक्रम में बेहद अहम और निर्णायक रही, हालांकि वह हमेशा पर्दे के पीछे ही रहे।

चागोस द्वीपसमूह की कहानी केवल भूगोल या रणनीति की नहीं, बल्कि न्याय, संप्रभुता और आत्मसम्मान की भी है। 1965 में जब मॉरीशस को ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिलने वाली थी, ठीक उसी वक्त ब्रिटेन ने इस द्वीपसमूह को मॉरीशस से अलग कर लिया और अपने अधीन रखा। इसके बाद हजारों स्थानीय निवासियों को जबरन उनके घरों से बेदखल किया गया और डिएगो गार्सिया द्वीप पर अमेरिका के लिए एक विशाल सैन्य अड्डा बनाया गया, जो आज भी अमेरिका के वैश्विक रणनीतिक ढांचे का अहम हिस्सा है। तब से मॉरीशस इस ज़मीन की वापसी की लड़ाई लड़ रहा था, जो अब जाकर सफल हुई है।

इस समझौते के तहत ब्रिटेन ने द्वीपसमूह की संप्रभुता मॉरीशस को लौटा दी है, लेकिन डिएगो गार्सिया को ब्रिटेन 99 साल की लीज पर अमेरिका के साथ मिलकर इस्तेमाल करता रहेगा। इसके बदले मॉरीशस को हर साल लगभग 101 मिलियन पाउंड की राशि दी जाएगी। यह व्यवस्था उस सैन्य संतुलन को भी बनाए रखेगी, जो हिंद महासागर में अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए रणनीतिक दृष्टि से जरूरी माना जाता है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा पहलू यह है कि आखिरकार उपनिवेशवाद के एक गहरे जख्म पर मरहम लगाया गया है।



मॉरीशस के प्रधानमंत्री
नवीन रामगुलाम ने
डिजिटल समारोह में
कहा कि भारत की
लगातार कूटनीतिक
सहायता और भरोसे ने
इस संघर्ष को मुकाम
तक पहुंचाया। उनके
अनुसार, चागोस की
वापसी केवल भूभाग की
वापसी नहीं, बल्कि
आत्म-सम्मान की
वापसी है और इसमें
भारत की भूमिका अमूल्य
रही।
— संजय सक्सेना



यह समझौता यूं ही नहीं हुआ। इसके पीछे कई सालों की बातचीत, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर हुई बहसों और चुपचाप की गई कूटनीति शामिल है। भारत की भूमिका यहां खासतौर पर ध्यान देने योग्य है। 2019 में जब अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने इस पूरे विवाद पर अपनी परामर्शी राय दी और ब्रिटेन के कब्जे को गैरकानूनी ठहराया, तब से लेकर अब तक भारत ने लगातार मॉरीशस के दावे का समर्थन किया। चाहे वह संयुक्त राष्ट्र महासभा में हो, या हिंद महासागर के देशों के समूहों में। भारत ने हर स्तर पर यह स्पष्ट किया कि चागोस मॉरीशस का अभिन्न अंग है और इसकी वापसी केवल समय की बात है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे मामले को केवल एक सहयोगी देश की मदद के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे 'ग्लोबल साउथ' यानी वैश्विक दक्षिण के देशों की आवाज़ को मजबूत करने और औपनिवेशिक इतिहास के खिलाफ एक नैतिक पहल के रूप में लिया। यही कारण है कि इस पूरे घटनाक्रम में भारत की भूमिका तो रही, लेकिन प्रचार या राजनीतिक लाभ की कोई होड़ नहीं देखी गई। भारत ने न तो कोई बड़ा आधिकारिक बयान जारी किया और न ही इसे अपनी कूटनीतिक जीत के तौर पर पेश किया। लेकिन मॉरीशस ने इस सहयोग को पूरे दिल से स्वीकारा और खुले तौर पर प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर धन्यवाद दिया।

मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम ने डिजिटल समारोह में कहा कि भारत की लगातार कूटनीतिक सहायता और भरोसे ने इस संघर्ष को मुकाम तक पहुंचाया। उनके अनुसार, चागोस की वापसी केवल भूभाग की वापसी नहीं, बल्कि आत्म-सम्मान की वापसी है और इसमें भारत की भूमिका अमूल्य रही। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस समझौते को 'एक ऐतिहासिक

चागोस द्वीपसमूह की वापसी कोई साधारण घटना नहीं है। यह इतिहास का वह मोड़ है जहां उपनिवेशवाद का एक दरवाज़ा बंद हुआ और वैश्विक न्याय का एक नया अध्याय शुरू हुआ। इस जीत में भारत की भूमिका एक मौन लेकिन मजबूत नींव की तरह रही और यह दिखाता है कि सच्ची कूटनीति हमेशा शोर नहीं मचाती, लेकिन इतिहास ज़रूर बदल देती है।

समाधान' करार दिया और कहा कि यह हिंद महासागर क्षेत्र में स्थायित्व, सहयोग और शांति के लिए मील का पत्थर साबित होगा।

इस समझौते के रास्ते में एक छोटा लेकिन संवेदनशील मोड़ भी आया, जब चागोस द्वीपसमूह की एक महिला नागरिक बर्टिस पॉप ने ब्रिटिश अदालत में याचिका दायर की कि यदि द्वीप मॉरीशस को सौंप दिए गए तो उन्हें वहां लौटने की अनुमति शायद न मिले। इस पर अदालत ने कुछ समय के लिए सौदे पर अस्थायी रोक लगा दी। लेकिन बाद में सुनवाई पूरी होने के बाद यह रोक हटा ली गई और समझौते पर अंततः हस्ताक्षर हो गए।

डिएगो गार्सिया द्वीप की बात करें तो यह अमेरिकी सेनाओं के लिए एक बेहद अहम ठिकाना है, खासकर अफगानिस्तान, ईरान और चीन की निगरानी के लिहाज़ से। इसलिए यह सौदा केवल ऐतिहासिक या भावनात्मक नहीं था, बल्कि इसमें रणनीतिक और सुरक्षा की भी कई परतें शामिल थीं। यही कारण है कि इसमें संतुलन साधना बेहद जरूरी था और भारत ने इसमें

बड़ी भूमिका निभाई।

यह सौदा 'न्यू वर्ल्ड ऑर्डर' यानी नए वैश्विक व्यवस्था की एक झलक भी देता है। आज जब पश्चिमी ताकतें अपने पुराने औपनिवेशिक पदचिह्नों को मिटा रही हैं, तब भारत जैसे देश सामने आकर न केवल साझेदारी निभा रहे हैं, बल्कि न्याय और नैतिक मूल्यों को केंद्र में रखकर अपनी भूमिका तय कर रहे हैं। यह केवल भूगोल का नहीं, वैश्विक मानसिकता का भी परिवर्तन है।

इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया है कि न्याय भले देर से मिले, लेकिन वह संभव है बशर्ते उसके लिए दृढ़ इच्छाशक्ति, निरंतर कूटनीतिक प्रयास और अंतरराष्ट्रीय सहयोग हो। चागोस की वापसी न केवल मॉरीशस की जीत है, बल्कि यह उन लाखों लोगों के लिए भी एक आशा की किरण है, जिनकी ज़मीनें, पहचान और अधिकार औपनिवेशिक साजिशों के चलते उनसे छीन लिए गए थे।

भारत के लिए यह एक अवसर भी है और एक जिम्मेदारी भी। अवसर इसलिए कि हिंद महासागर में उसका प्रभाव और अधिक स्थिर और स्वीकार्य हुआ है। जिम्मेदारी इसलिए कि अब जब भारत 'ग्लोबल साउथ' की आवाज़ बनना चाहता है, तो उसे आगे भी ऐसे ही मुद्दों पर न्याय और नैतिकता के पक्ष में खड़े रहना होगा चाहे वह अफ्रीका के किसी छोटे देश की बात हो या दक्षिण एशिया के किसी द्वीप राष्ट्र की।

चागोस द्वीपसमूह की वापसी कोई साधारण घटना नहीं है। यह इतिहास का वह मोड़ है जहां उपनिवेशवाद का एक दरवाज़ा बंद हुआ और वैश्विक न्याय का एक नया अध्याय शुरू हुआ। इस जीत में भारत की भूमिका एक मौन लेकिन मजबूत नींव की तरह रही और यह दिखाता है कि सच्ची कूटनीति हमेशा शोर नहीं मचाती, लेकिन इतिहास ज़रूर बदल देती है। □□

घटती गरीबी: बढ़ते धन कुबेर



वैश्विक स्तर पर वित्तीय संस्थान अब यह स्पष्ट रूप से मानने लगे हैं कि विश्व में भारत की आर्थिक ताकत बहुत तेजी से बढ़ रही है। हाल ही में जारी किए गए एक सर्वे रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत में पिछले बीते वर्ष में उच्च नेटवर्थ व्यक्तियों की संख्या एवं उनकी संपत्तियों में अतुलनीय वृद्धि दर्ज हुई है। जबकि विश्व के कई देशों विशेष रूप से विकसित देशों में उच्च नेटवर्थ व्यक्तियों की संख्या एवं इनकी सम्पत्ति में वृद्धि दर लगातार नीचे गिर रही है। इसका आशय तो अब यही लगाया जा सकता है विश्व में आर्थिक शक्ति अब पश्चिम से पूर्व की ओर स्थानांतरित हो रही है।

भारत में जिस व्यक्ति की शुद्ध सम्पत्ति 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक होती है उसे उच्च नेटवर्थ व्यक्ति (एचएनडब्ल्यूआई) कहा जाता है। पिछले वर्ष भारत में उच्च नेटवर्थ व्यक्तियों की औसत सम्पत्ति 8.8 प्रतिशत की दर से बढ़ी है, जबकि विश्व में यह औसतन 2.6 प्रतिशत की दर से बढ़ी है। इसका परिणाम यह हुआ है कि भारत में मिलिनेयर्स की संख्या बढ़कर 378,810 हो गई है और इनकी कुल सम्पत्ति 1.5 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर अर्थात् 129 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गई है। वर्ष 2024 में भारत में 4,290 अल्ट्रा उच्च नेटवर्थ व्यक्ति निवास कर रहे थे, जिनकी कुल सम्पत्ति 53,477 करोड़ अमेरिकी डॉलर थी। अल्ट्रा उच्च नेटवर्थ व्यक्ति उस नागरिक को कहते हैं जिसकी शुद्ध सम्पत्ति 3 करोड़ अमेरिकी डॉलर अथवा उससे अधिक होती है।



आगे आने वर्षों में भी यदि इसी प्रकार के आर्थिक विकास दर भारत में लागू रहती है तो बहुत सम्भव है कि कुछ ही वर्षों के उपरांत संभवतः भारत में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला एक भी नागरिक शेष नहीं रहेगा।
— प्रहलाद सबनानी

भारत में तो उच्च नेटवर्थ व्यक्तियों की संख्या बढ़ी है परंतु यूरोप में इनकी संख्या 2.1 प्रतिशत घटी है। ब्रिटेन में 14,000, फ्रान्स में 21,000, जर्मनी में 41,000 उच्च नेटवर्थ व्यक्तियों की संख्या घटी है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में उच्च नेटवर्थ व्यक्तियों की संख्या 1.7 प्रतिशत बढ़ी है तो लेटिन अमेरिका में उच्च नेटवर्थ व्यक्तियों की संख्या 8.5 प्रतिशत घटी है। साथ ही, मध्य पूर्व में भी उच्च नेटवर्थ व्यक्तियों की संख्या में 2.1 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।

क्या भारत में उच्च नेटवर्थ व्यक्तियों की बढ़ती संख्या एवं इनकी बढ़ती सम्पत्ति से भारत में कहीं आर्थिक असमानता के गहराने का संकट तो खड़ा नहीं हो रहा है? हालांकि भारत में उच्च नेटवर्थ व्यक्तियों की बढ़ती सम्पत्ति, भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत का प्रतीक भी है। परंतु, यदि इस बढ़ी हुई सम्पत्ति का लाभ समाज के समस्त नागरिकों को नहीं मिल पा रहा है तो यह सोचनीय प्रश्न अवश्य है।

इसी संदर्भ में हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में अत्यधिक गरीबी में जीवन यापन करने वाले नागरिकों की संख्या में अतुलनीय रूप से कमी दर्ज की गई है। यह भारत के लिए निश्चित ही बहुत अच्छी खबर हो सकती है। इस

रिपोर्ट के अनुसार, भारत में अत्यधिक गरीबी में जीवन यापन करने वाले नागरिकों की संख्या 34.44 करोड़ नागरिकों से घटकर 7.52 करोड़ नागरिक रह गई है। भारत में लगभग 27 करोड़ नागरिकों को अत्यधिक गरीबी से ऊपर ले आया जा सका है। विश्व बैंक की उक्त रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011-12 में भारत की कुल जनसंख्या का 27.1 प्रतिशत नागरिक अत्यधिक गरीबी में जीवन यापन करने को मजबूर था परंतु वर्ष 2022-23 आते आते यह संख्या घटकर मात्र 5.3 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई है, जबकि, इस बीच भारत की जनसंख्या में भी वृद्धि हुई है। यह भारत में तेज गति से विकसित किए गए रोजगार के अवसरों के चलते सम्भव हो सका है। इस संदर्भ में विशेष रूप से केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई विभिन्न योजनाओं के लाभ को देश की अधिकतम जनसंख्या तक पहुंचाने के कारण भारत में बहुआयामी गरीबी को कम करने में अपार सफलता हासिल की जा सकी है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) वर्ष 2005-06 में 53.8 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2022-23 में 15.5 प्रतिशत तक नीचे आ गया है। आगे आने वर्षों में भी यदि इसी प्रकार के आर्थिक विकास दर भारत में लागू रहती है तो बहुत सम्भव है कि कुछ ही वर्षों के उपरांत संभवतः भारत में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला एक भी नागरिक शेष नहीं रहेगा।

विश्व बैंक की उक्त रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को कम करने में लगभग एक जैसी सफलता मिली है। इसी का परिणाम है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक गरीबी दर आज 18.4 फीसदी से घटकर 2.8 प्रतिशत रह गई है। इसी तरह से शहरी क्षेत्रों में भी अत्यधिक गरीबी दर जो 10.7 फीसदी के करीब थी, वह घटकर

सिर्फ 1.1 पर आ गई है। इसी तरह का एक व्यापक अंतर ग्रामीण-शहरी जीवन के आर्थिक व्यवहार में भी दूर हुआ है, यह अंतर 7.7 फीसदी से घटकर सिर्फ 1.7 प्रतिशत पर आ पहुंचा है। विशेष रूप से महिलाओं के बीच रोजगार के अवसरों में अतुलनीय वृद्धि दर हासिल की जा सकी है। ग्रामीण इलाकों में कृषि के क्षेत्र में महिलाओं को रोजगार के अवसरों में वृद्धि दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में शहरी क्षेत्रों के बेरोजगारी की दर 6.6 प्रतिशत तक नीचे आ गई है, जो वर्ष 2017-18 के बाद से सबसे कम है।

भारत में गरीबी दूर करने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों ने मिलकर काम किया है। इस सम्बंध में विशेष रूप से केंद्र सरकार द्वारा कई योजनाएं लागू की गई हैं। इन महत्वपूर्ण एवं विशेष योजनाओं में शामिल हैं — प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना, जैसी अनेक योजनाओं ने देश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे नागरिकों को बहुत अधिक लाभ पहुंचाया है, जिससे इन्हें गरीबी रेखा के ऊपर लाया जा सका है। इसी प्रकार, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, डिजिटल क्रांति, मेक इन इंडिया, जन औषद्धि केंद्र, विभिन्न फसल की एमएसपी पर खरीदी एवं इसके माध्यम से किसानों को आय की गारंटी देना, मखाना बोर्ड का गठन, जनजातियों का सशक्तिकरण — ग्राम समृद्धि, दालों में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन चलाना, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ग्रामीण विद्युत आपूर्ति, किसानों को किफायती दरों पर यूरिया उपलब्ध कराना, भारत को पंख (उड़ान 2

की उड़ान और तेज हुई), विमानन के क्षेत्र में नए युग का प्रारम्भ, आदि क्षेत्रों में लागू की गई उक्त वर्णित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जो अतुलनीय कार्य किए गए हैं, उससे देश में रोजगार के करोड़ों नए अवसर निर्मित करने में सफलता हासिल की जा सकी है।

उक्त वर्णित विभिन्न योजनाओं को लागू करने में केंद्र सरकार ने कभी भी वित्त की कमी नहीं आने दी क्योंकि करों की वसूली में ईमानदारी एवं वित्तीय अनुशासन के चलते जीएसटी, आय कर एवं कारपोरेट करों में उच्च स्तरीय वृद्धि दर्ज हुई है। न केवल उक्त वर्णित विभिन्न योजनाओं को लागू करने के लिए पर्याप्त वित्त की उपलब्धता बनी रही है बल्कि पूंजीगत खर्चों में भी अतुलनीय वृद्धि दर्ज की जा सकी है। साथ ही, बजट में वित्तीय घाटे को भी लगातार कम करने में सफलता हासिल हुई है। और तो और, केंद्र सरकार के विभिन्न उपक्रमों की कार्यप्रणाली में इस प्रकार से सुधार किया गया है कि जो उपक्रम पिछले कुछ वर्षों पूर्व तक घाटे में चल रहे थे एवं केंद्र सरकार को इन उपक्रमों को चलायमान बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता उपलब्ध करानी होती थी, आज ये उपक्रम केंद्र सरकार के लिए कमाऊ पूत साबित हो रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में तो केंद्र सरकार के विभिन्न उपक्रमों ने 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि का लाभ अर्जित किया है। इन सभी कारणों से केंद्र सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा आम नागरिकों के भले के लिए लागू की गई विभिन्न योजनाओं को चालू रखने में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना करना नहीं पड़ा है एवं जिसके चलते गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे करोड़ों नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार करने में अपार सफलता मिली है। □□

(प्रहलाद सबनानी: सेवानिवृत्त उपमहाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, ग्वालियर, म.प्र.)

प्रकृति बनाम विकास



प्रकृति को मानव निर्मित चीजों को छोड़कर हर चीज के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो हमें पेड़ों, पौधों, जानवरों, पर्यावरण और हर उस चीज से घेरती हैं जो मानव निर्मित नहीं है। प्राकृतिक साधनों से हमें जो कुछ भी प्रदान किया जाता है वह प्रकृति में शामिल है। “प्रकृति” भौतिक दुनिया की घटनाओं को संदर्भित करती है, और सामान्य रूप से जीवन के लिए भी। यह उप-परमाणु तत्वों से लेकर ब्रह्मांडीय उत्पादों तक के पैमाने पर फैली है। प्रकृति मानव जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और हमें जीवन के कुछ आवश्यक तत्व जैसे भोजन, पानी, हवा आदि प्रदान करती है। आज

प्रकृति को भूविज्ञान के साथ-साथ हमारे आसपास के वन्यजीवों के व्यापक अर्थों में वर्गीकृत किया गया है। प्रकृति में प्राकृतिक वातावरण या जंगल-जंगली जानवर, चट्टानें, जंगल, समुद्र तट और सामान्य चीजें भी शामिल हैं जो मानव हस्तक्षेप के बावजूद काफी हद तक परिवर्तित नहीं हुई हैं, या जो मानव हस्तक्षेप के बावजूद बनी रहती हैं यानी मानव का सरल तरीके से इसके अस्तित्व में कोई भूमिका नहीं है।

प्रकृति शब्द लैटिन शब्द “नटुरा”, या “आवश्यक गुण, जन्मजात स्वभाव” से लिया गया है। प्राचीन काल में, शाब्दिक अर्थ “जन्म” है। नटुरा ग्रीक शब्द फिसिस का एक लैटिन अनुवाद था, जो मूल रूप से आंतरिक विशेषताओं से संबंधित था जो पौधों, जानवरों और दुनिया की अन्य विशेषताओं से संबंधित थे जो अपने स्वयं के समझौते का विकास करते हैं। मनुष्यों के आसपास की बहुत सी चीजें प्रकृति में शामिल हैं। आज शब्द के विभिन्न उपयोगों के भीतर, “प्रकृति” अक्सर भूविज्ञान और वन्यजीवों को संदर्भित करता है। प्रकृति विभिन्न प्रकार के जीवित पौधों और जानवरों के सामान्य दायरे का उल्लेख कर सकती है, और कुछ मामलों में निर्जीव वस्तुओं से जुड़ी प्रक्रियाओं के लिए – जिस तरह से विशेष प्रकार की चीजें मौजूद हैं और अपने स्वयं के समझौते में परिवर्तन, जैसे कि मौसम और भूविज्ञान पृथ्वी, और वह ऊर्जा जिसमें से ये सभी चीजें बनी हैं।



आज की जरूरत यह
महसूस करना है कि
हमारे प्राकृतिक
वातावरण को प्रमुखता से
संरक्षित करते हुए हमारी
प्रकृति को नुकसान
पहुंचाए बिना विकास
प्रक्रिया को पूरा करने के
तरीके अपनाए जाएं।
— विजय गर्ग

विकास को विशिष्ट मानवीय मांगों और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के व्यवस्थित उपयोग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है और इसमें मौजूदा स्रोतों में सुधार और उन्नयन को जोड़ने की प्रक्रिया भी शामिल है। बढ़ती आबादी और मानव लालच के कारण भोजन, पानी, ऊर्जा और खनिजों की दुनिया की आवश्यकता दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। जनसंख्या वृद्धि, अनियंत्रित विकास और जलवायु परिवर्तन के साथ संयुक्त ये मांगें प्राकृतिक पर्यावरण पर और भी अधिक दबाव डाल रही हैं। इसलिए अपनी भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए, हमें अपनी भूमि और पानी की रक्षा, प्रबंधन और विकास के बारे में अब होशियार निर्णय लेने होंगे।

विकास एक प्राकृतिक घटना है, यहां तक कि प्रकृति भी विकास का समर्थन करती है और हर प्राकृतिक चीज विकसित होती है। मनुष्य एक बच्चे से एक बड़े आदमी तक विकसित होता है, छोटे पौधे बड़े पेड़ों में विकसित होते हैं और इसी तरह, और मूल विचार यह है कि प्रकृति विकासात्मक प्रक्रिया का विरोध नहीं करती है। आज मनुष्यों ने हमारे पहाड़ों, रेगिस्तानों, मैदानों, महासागरों और नदियों को विकासात्मक उद्देश्य के लिए उपलब्ध प्राकृतिक क्षेत्र की खोज की है और लगातार खनन, बुनियादी ढांचे के विकास, निर्माण और जंगलों को काटने जैसी गतिविधियों को अंजाम दिया है जो हमारे प्राकृतिक वातावरण के लिए एक बड़ा खतरा है।

प्रकृति और विकास प्रकृति और विकास दो अलग-अलग शाखाएं हैं लेकिन फिर भी एक-दूसरे से बहुत निकटता से जुड़ी हुई हैं। विकास और पर्यावरण को पारंपरिक रूप से अलग से प्रबंधित किया गया है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से, शोधकर्ता लगातार इस बात पर काम कर रहे हैं कि कैसे इन दोनों को समृद्धि बढ़ाने और एक ही समय में ग्रह की रक्षा के लिए सामंजस्य बनाया जा सकता है। विकास और प्रकृति को पारंपरिक रूप से अलग-अलग शैक्षणिक विषयों, अलग-अलग सरकारी एजेंसियों और अलग-अलग कानूनों और नीतियों द्वारा नियंत्रित किया गया है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में तेजी से विकासात्मक गतिविधियों और हमारे प्राकृतिक पर्यावरण के निरंतर क्षरण ने विकास प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक समाधान खोजने के लिए मजबूर किया है।

यह देखा गया है कि आर्थिक विकास अक्सर लोगों को सामान और सेवाएं प्रदान करने की प्रकृति की क्षमता की कीमत पर आगे बढ़ता है। दुनिया भर में बीस प्रतिशत वन क्षेत्र को

लकड़हारे, किसानों और रैंचर्स द्वारा अपवित्र किया गया है, जो हमारे ग्रह के फेफड़ों की क्षमता के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में रीसायकल करना, हमारी हवा को साफ करना और क्षेत्रीय और वैश्विक जलवायु को विनियमित करना वास्तव में मुश्किल हो रहा है। इन दिनों प्रमुख नदियों में तेजी से औद्योगिकीकरण और उनके कचरे को नदियों में फैलाने के कारण जल प्रदूषण और विषाक्त से भरी भावनाओं जैसी पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कई अन्य गतिविधियाँ जैसे खनन, जंगल काटना, ईंधन जलाना आदि। ऐसे काम हमारे पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं और प्राकृतिक संसाधनों के प्रदूषण और कमी के लिए भी अग्रणी हैं।

विकास की तेजी से प्रक्रिया के साथ प्रकृति और विकास के बीच एक संतुलन बनाना जरूरी है। हम प्रकृति पर अपनी गतिविधियों के हानिकारक प्रभावों की उपेक्षा कर रहे हैं। मुनाफे को बढ़ाने के लिए बहुत सारे उद्योगपति विभिन्न पर्यावरण कानूनों की उपेक्षा कर रहे हैं और केवल अपना मुनाफा कमाने लगे हैं। समय की आवश्यकता कुछ प्रकृति के अनुकूल तकनीकों का अभ्यास करना है ताकि विकासात्मक प्रक्रिया हमारे प्राकृतिक वातावरण से समझौता किए बिना आगे बढ़े। नागरिक की दीर्घकालिक दृष्टि और बहु-पीढ़ीगत मूल्यों ने कस्बों में जीवन और जीवन की एक उच्च गुणवत्ता बनाई है जो उल्लेखनीय रूप से अद्वितीय और सुंदर है। लेकिन चिंता की बात यह है कि हमारा क्षेत्र बदल रहा है। तेजी से विकास और ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में जाने वाले बहुत से लोगों के कारण, इसने प्रमुख शहरों में बहुत भीड़ पैदा की है, जिसके परिणामस्वरूप शहर हर दिन नए निवासियों के साथ आ रहे हैं, जिससे

प्राकृतिक संसाधनों का अधिक उपयोग हो रहा है। इस प्रकार प्राकृतिक क्षेत्रों, वन्यजीव आवास, स्वच्छ नदियों और धाराओं पर दबाव बढ़ रहा है। संरक्षण और जीवन क्षमता के साथ विकास और विकास को संतुलित करने के अभिनव तरीकों का पता लगाने की एक बड़ी आवश्यकता है।

प्रकृति के अनुकूल व्यवहार प्राकृतिक प्रणालियों और हाइड्रोलॉजिक संसाधनों के संरक्षण के लिए प्रकृति के अनुकूल प्रथाओं को अपनाना बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे पर्यावरण को बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है और पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपना कर्तव्य निभाना प्रत्येक मानव का कर्तव्य है। हमारा पर्यावरण हमें स्वच्छ और ताजी हवा, पानी, भोजन और फल आदि प्रदान करता है। इसलिए यह हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम इसके उद्धारकर्ता के रूप में कार्य करें। हम सभी सामुदायिक स्तर के साथ-साथ व्यक्तिगत स्तर पर एक या दूसरे तरीके से अपनी प्रकृति को बचाने में योगदान कर सकते हैं।

आज की जरूरत यह महसूस करना है कि हमारे प्राकृतिक वातावरण को प्रमुखता से संरक्षित करते हुए हमारी प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना विकास प्रक्रिया को पूरा करने के तरीके अपनाए जाएं। ऐसे निर्णय लेना महत्वपूर्ण है जो महत्वपूर्ण प्राकृतिक क्षेत्रों को विकसित करने के तरीके को बदल सके और प्रकृति संरक्षण को सरकारों, कंपनियों और समुदायों को अंतरिक्ष का उपयोग करने और साझा करने, प्राकृतिक क्षेत्रों की रक्षा करने, संसाधन प्रबंधन में सुधार करने और निवेश करने में सक्षम बनाने के लिए विज्ञान को विकसित कर सके। सरकारें भी एक स्थायी भविष्य के लिए अधिक बुद्धिमानी से निवेश करें। □□

(विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्राचार्य शैक्षिक स्तंभकार प्रख्यात शिक्षाविद्
स्ट्रीट कोर बंद एमएचआ मलोट पंजाब)

किसानों की आमदनी बढ़ाने का जरिया है पीएम कुसुम योजना



योजना की खास बातें हैं कि किसान अपनी बंजर या खेती के लायक नहीं बची जमीन पर 500 किलो वाट से 2 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र लगा सकते हैं, इससे उत्पादित ऊर्जा को ग्रिड में बेंचकर पैसा कमा सकते हैं, किसान डीजल और बिजली से चलने वाले पंपों को सोलर पावर वाले पंपों में बदल सकते हैं।
— शिवनंदन लाल

सिंचाई की कमी, भूमि क्षरण, जलवायु परिवर्तन, आधुनिक तकनीक का अभाव और कमजोर वित्तीय स्थिति के बीच खेतों में अपना जांगर तोड़ मेहनतकर देश के लोगों का पेट भरने वाले कृषि प्रधान भारत देश के किसानों को अगर समय पर बिजली नहीं मिलती है तो उन्हें कई अन्य तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसका असर फसलों के उत्पादन पर भी नजर आता है। ऐसे में किसानों की इस समस्या से निपटने के लिए सरकार की ओर से कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। देश के किसानों को खेती के लिए किसी नए कर्ज के बोझ तले दबना ना पड़े इसके लिए कई तरह की कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। इस कड़ी में सरकार की ओर से पीएम कुसुम योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए सब्सिडी मुहैया कराई जाती है। पीएम कुसुम योजना के जरिए किसान मात्रा 10 प्रतिशत पैसा देकर महंगे सोलर उपकरण लगवा सकते हैं और मुफ्त की बिजली पा सकते हैं। किसान इस योजना के तहत जहां 70 से 80 फीसदी सब्सिडी पर सोलर पंप अपने खेत में लगवा सकते हैं। वहीं इसके जरिए वे बेहतर कमाई भी कर सकते हैं।

देश के नागरिक यदि सोलर ऊर्जा से शुरू करना चाहते हैं तो फिर सरकार की पीएम कुसुम योजना के साथ जुड़ने की सोच सकते हैं। इस योजना के तहत किसानों को अपनी जमीन पर सोलर पैनल लगाने के लिए सिर्फ 10 फीसदी पैसे खर्च करना होता है। सोलर पंप के जरिए किसान अपने खेतों की सिंचाई ही नहीं कर सकते हैं। बल्कि बंजर जमीन में इसे लगाकर मोटी कमाई भी कर सकते हैं। जानकारों के मुताबिक, एक मेगावाट का सोलर प्लांट लगाने के लिए करीब 4 से 5 एकड़ भूमि की जरूरत होती है। इससे एक साल में करीब 15 लाख बिजली यूनिट बनाई जा सकती है। इस बिजली को किसान बेच सकते हैं। जिससे किसानों की मोटी कमाई होगी।

मालूम हो कि केंद्र की एनडीए सरकार ने साल 2019 में प्रधानमंत्री कुसुम योजना की शुरुआत की थी। जिसके बाद इस योजना का विस्तार किया गया है। यह योजना ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से चलाई जा रही है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से 30 फीसदी और राज्य सरकार की तरफ से 45 फीसदी सब्सिडी मुहैया कराई जाती है। कुल मिलाकर किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए 75 फीसदी सब्सिडी मिल जाती है। किसानों को सिर्फ 25 फीसदी पैसे देने होते हैं। वहीं बैंक की ओर से लोन भी मिलता है। इस लोन को किसान अपनी होने वाली आमदनी से आसानी से चुका सकते हैं। इन पंपों को लगाने पर बीमा कवर भी मिलता है। इस योजना का मकसद सौर ऊर्जा से चलने वाले सोलर पंप को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत सरकार की ओर से अब तक साढ़े 3 करोड़ से अधिक सोलर पंप किसानों को दिए जा चुके हैं।

भारत की ऊर्जा सुरक्षा, देश की आर्थिक और पर्यावरणीय रणनीति की आधारशिला है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा और आत्मनिर्भरता पर विशेष जोर दिया गया है। जनवरी 2025 तक, देश की गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता 217.62 गीगामेंट तक पहुँच गई है। सीसीडीसी पवन पहल ने पवन ऊर्जा विकास को काफी विस्तार दिया है, जिससे इस क्षेत्र की स्थापित

क्षमता 48.16 गीगावॉट हो गई है। 2023 में शुरू किया गया राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के साथ भारत को हाइड्रोजन ऊर्जा में विश्व के अग्रणी देश के रूप में स्थापित कर रहा है। राष्ट्रीय सौर मिशन ने सौर ऊर्जा विकास को बढ़ावा दिया है, जिसकी स्थापित क्षमता 2016 के 9.01 गीगावॉट से बढ़कर 2025 में 97.86 गीगावॉट हो गई है। इसके अतिरिक्त, पीएम-कुसुम और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना किसानों और परिवारों के बीच सौर ऊर्जा अपनाने में तेजी ला रही है। पर्याप्त सरकारी निधि और नीतिगत उपायों द्वारा समर्थित ये प्रयास, कार्बन उत्सर्जन को कम करते हुए ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करने की भारत की प्रतिबद्धता को उजागर करते हैं। तकनीकी प्रगति और रणनीतिक निवेश का लाभ उठाकर, भारत एक स्वच्छ, अधिक सुदृढ़ ऊर्जा भविष्य की ओर अग्रसर है।

भारत की ऊर्जा सुरक्षा, देश के आर्थिक विकास और सतत विकास लक्ष्यों का एक महत्वपूर्ण घटक है। सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने, ग्रिड स्थिरता को बढ़ाने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं पर तेज गति से काम कर रही हैं। राष्ट्रीय जैव ऊर्जा मिशन, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, पीएम-कुसुम और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसे प्रमुख कार्यक्रम स्वच्छ और आत्मनिर्भर ऊर्जा भविष्य के प्रति देश की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। जनवरी 2025 तक, भारत की कुल गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता 21762 गीगावॉट तक पहुंच गई है।

जून 2020 में शुरू की गई, केंद्रीकृत डेटा संग्रह और समन्वय (सीसीडीसी) पवन पहल का उद्देश्य सटीक डेटा संग्रह और अनुसंधान के माध्यम से पवन संसाधन मूल्यांकन में

सुधार करके भारत के पवन ऊर्जा विकास को आगे बढ़ाना है। यह पहल परियोजना डेवलपर्स के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, जिससे उन्हें पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए सबसे उपयुक्त स्थानों की पहचान करने में मदद मिलती है। यह बड़े पैमाने की पवन ऊर्जा परियोजनाओं के कुशल कार्यान्वयन का समर्थन करता है और पवन क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करता है। सरकार ने राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान (एनआईडब्ल्यू) के माध्यम से पूरे देश में 800 से अधिक पवन-निगरानी स्टेशन स्थापित किए हैं और जमीनी स्तर से 50 मीटर, 80 मीटर और 100 मीटर ऊपर पवन क्षमता मानचित्र जारी किए हैं। 30 जनवरी 2024 तक, भारत की संचयी पवन ऊर्जा क्षमता 48.16 गीगावॉट है।

योजना का प्रमुख लक्ष्य केंद्रीकृत डेटा संग्रह और अनुसंधान के माध्यम से पवन ऊर्जा विकास को सुविधाजनक बनाना, बेहतर कार्यस्थल पहचान के लिए सटीक पवन संसाधन मूल्यांकन प्रदान करना, पवन ऊर्जा परियोजनाओं में निजी क्षेत्र के निवेश और सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना है।

अब तक की उपलब्धियां की बात करें तो उन्नत पवन संसाधन मानचित्रण ने देश भर में 50 से अधिक संभावित पवन ऊर्जा स्थलों की सफल पहचान में योगदान दिया है।

2020-2024 से 10 गीगावॉट से अधिक नई पवन ऊर्जा क्षमता के विकास में योगदान दिया, जिससे भारत की पवन ऊर्जा क्षमता में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

पवन ऊर्जा क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि, मार्च 2004 के 1.86 गीगावॉट और दिसंबर 2014 के 21.04 गीगावाट से बढ़कर जनवरी 2025 में 48.16 गीगावॉट, जो पहल के प्रभाव को दर्शाती है।

2024 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत

की पहली अपतटीय पवन उर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए 7,453 करोड़ रुपये की व्यवहार्यता अंतर निधि (वीजीएफ) योजना को मजूरी दी। इस योजना में 1 गीगावॉट की अपतटीय पवन क्षमता (गुजरात और तमिलनाडु के तटों पर 500-500 मेगावाट) के लिए 6.853 करोड़ रुपये और इन परियोजनाओं के लॉजिस्टिक्स का समर्थन करने के क्रम में बंदरगाह उन्नयन के लिए 600 करोड़ रुपये शामिल हैं।

पीएम कुसुम योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाले सिंचाई पंप मुहैया कराना ताकि उनकी कृषि उत्पादन लागत कम हो, डीजल पंप की जगह सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप इस योजना के तहत दिए जाते हैं, अगर किसान अतिरिक्त बिजली का उत्पादन करते हैं तो वह उसे बेचकर पैसा भी कमा सकते हैं तथा स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देकर कार्बन उत्सर्जन को कम करना है।

योजना की खास बातें हैं कि किसान अपनी बंजर या खेती के लायक नहीं बची जमीन पर 500 किलो वाट से 2 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र लगा सकते हैं, इससे उत्पादित ऊर्जा को ग्रिड में बेचकर पैसा कमा सकते हैं, किसान डीजल और बिजली से चलने वाले पंपों को सोलर पावर वाले पंपों में बदल सकते हैं।

अधिकांश मामलों में सरकार पीएम कुसुम योजना के तहत 60 प्रतिशत सब्सिडी देती है जबकि 30 प्रतिशत बैंक से ऋण लिया जा सकता है किस को सिर्फ 10 प्रतिशत ही अपनी तरफ से देना होता है। मान लीजिए कि अगर 50000 का पंप है तो 5000 का इंतजाम कर किसान इसका लाभ उठा सकता है। अमूमन सोलर पैनल 25 साल तक चलते हैं इससे लंबे समय तक किसानों को लाभ मिलता है। □□

विकसित भारत की संकल्पना और कौशल विकास

वर्ष 2047 आजादी का शताब्दी वर्ष होगा, तब भारत को दुनिया के नक्शे पर अति विकसित भारत के रूप में देखने जाने का सपना साकार होगा। सरकार इस हेतु प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। देश के नागरिकों को भी अपने श्रम की आहुति देनी होगी। हमें अपनी वार्षिक वृद्धि दर बढ़ानी होगी। आर्थिक विशेषज्ञ 2024-25 के अनुसार एक दशक तक आर्थिक वृद्धि दर को 8 प्रतिशत तक रखना होगा। वृद्धि दर 2023-24 में हम पा चुके हैं। 2024-25 में अपेक्षित आर्थिक वृद्धि दर 6.4 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। 2022 से 2027 तक के 25 वर्षों में आजादी के अमृत काल के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। इसी अवधि में दुनिया के विकसित देशों के साथ हमें खड़ा होना होगा, जिससे कि हमारी प्रति व्यक्ति आय विकसित देशों के समान या आसपास हो सके।

विकसित भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिये अमृत काल में छह महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाना उपयुक्त है – (अ) निजी क्षेत्र को बढ़ावा, (ब) सूक्ष्म, लघु, मध्यम, उद्योगों का विकास, (स) कृषि को विकास के इंजन के रूप में स्वीकारना, (द) हरित बदलाव योजना का वित्त पोषण, (य) शिक्षा व रोजगार के मध्य अन्तर कम करना, (क) राज्यों का क्षमता निर्माण करना। सरकार द्वारा 2022 में विकसित भारत की जो कल्पना की गई है, उसमें 2047 तक (25 वर्षों में) भारत को विकसित बनाना है। इसके लिये हमें कृषि, उद्योग, व्यापार बुनियादी ढांचे और अधिक निर्माण एवं विनिर्माण आदि क्षेत्रों को विकसित करना होगा। इसके लिये भारत सरकार और राज्य सरकारें सतत प्रयत्नशील हैं। 2022 से पहले से ही चल रही नवाचार मुद्रा योजना, लॉजिस्टिक्स हब, इन्क्यूबेटर समिट, एम.एस.एम.ई की योजनायें, मेक इन इंडिया, साइनिंग इंडिया आदि भारत को विकास पथ पर बहुत आगे ले जाना चाहती हैं। उसके लिये प्रयास जारी है।



विकसित भारत मिशन,
कौशल विकास पर
आधारित है। कौशल
और हुनर के साथ हमारे
युवा नवाचारों, तकनीकी
के माध्यम से देश के
उपलब्ध प्राकृतिक और
वित्तीय संसाधनों का
जितना अनुकूलतम
प्रयोग करेंगे उतना ही
राष्ट्र आगे बढ़ेगा।
— डॉ. जयप्रकाश मिश्र

विकसित और समृद्ध भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिये हमें वैश्विक कौशल को विकसित करना पड़ेगा। हमें वह कौशल या स्किल विकसित करने के लिये वैश्विक स्तर की नीतियों का अध्ययन करते हुये देश के संसाधनों की उपलब्धता के साथ विकास का मॉडल तैयार करने की आवश्यकता पर बल देना पड़ेगा। अग्रणी तकनीकी सीखने के लिये नवाचार अपनाना पड़ेगा। आज जब सम्पूर्ण भारत ही टेक्नीकल हब बनने के लिये प्रयासरत है तब कौशल विकसित करने के लिये वातावरण बना हुआ है इसके प्रमाण के लिये यह स्लोगन उपयुक्त है – ‘जब गाँव-गाँव में इंटरनेट और शहर में हो बाई-फाई, तो भला हिन्दुस्तान विकास की दुनिया में क्यों न हो हाई-फाई’

उक्त स्लोगन इस बात का प्रमाण दे रहा है कि तकनीकी के क्षेत्र में देश में प्रतिदिन नवाचार या नवउद्यम हो रहे हैं। तकनीकी का प्रयोग कर कौशल विकसित करना ही भारत का 2047 का विजन, विकसित भारत का मिशन पूर्ण होगा जब जनसंख्या को मानव संसाधन या कौशल से पूर्णतः श्रम शक्ति में परिवर्तित करना पड़ेगा। कौशल के माध्यम से जो जनसंख्या को मानव संसाधन या मानव शक्ति के रूप में परिवर्तित करता है। दुनिया के जिन देशों के पास बाइलड मानव शक्ति है वह देश विकास में जितने भी अनुशासित श्रमिक हैं इनको कुशल श्रमिक बनाने के लिये योजनायें बनाई गई हैं। इन योजनाओं का लाभ लेकर प्रशिक्षण प्राप्त करके कौशल विकसित करना और कराना हम सबका दायित्व है तभी विकसित भारत बन पायेगा।

किसी भी देश में विकास के तीन महत्वपूर्ण आयाम होते हैं – प्राकृतिक संसाधन, वित्तीय संसाधन एवं मानवीय संसाधन। प्राकृतिक और वित्तीय संसाधन निष्क्रिय संसाधन हैं। मानवीय संसाधन ही सक्रिय संसाधन है। इसलिये मानवीय संसाधन और इसके कौशल की व्याख्या ही सम्पूर्ण दुनिया में केन्द्रित है। किसी भी देश का विकास मैन, मनी एवं मेटेरियल पर ही केन्द्रित है – **Man** (मानवीय संसाधन), **Money** (वित्तीय संसाधन) एवं **Material** (भौतिक या प्राकृतिक संसाधन)

विकास को इन तीनों माध्यमों की गणितीय रूप से भी समझा जा सकता है—

D = m3k(s) **D = Development** या विकास, **m3 = man, money, Material** **K = knowledge** ज्ञान **S = Skill** कौशल।

वित्तीय और प्राकृतिक संसाधन कौशल विकसित करने का कोई माध्यम नहीं है मनुष्य के पास मस्तिष्क है जो कौशल विकसित करने का मानव संसाधन है। अतः किसी भी देश के विकास में मानवीय संसाधन ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वह प्राकृतिक और वित्तीय साधनों का भी दोहन और शोषण करता है।

Man (m1) = SKILL (कौशल) के प्रत्येक अक्षर को भी इस पेपर में परिभाषित किया गया है –

S = Systematic व्यवस्थित
K = Knowledge ज्ञान
I = Is & Intellectual बौद्धिक
("जीवन में व्यवस्थित ज्ञान की बौद्धिक सीख")

L = Learning सीख
L = Life जीवन
"Systematic Knowledge is intellectual learning of life"

जो देश अन-स्किल (ज्ञान रहित मनुष्य) को स्किल (ज्ञान सहित मनुष्य) में परिवर्तित कर ले गये उन्होंने अपने

मानवीय कौशल से अपने देश के प्राकृतिक और वित्तीय संसाधनों का दोहन किया। वे दुनिया के अन्य देशों के प्राकृतिक और वित्तीय संसाधनों का भी दोहन किया। कौशल समझदारी एवं आजीविका समझदारी के लिये ज्ञान जागरूकता आवश्यक होता है।

मध्य प्रदेश ने कौशल विकास के लिये 2021 के पश्चात जो नवाचार शुरू किया है वह कौशल विकसित करने के लिये अच्छा माध्यम है –

(1) मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना – राज्य शासन ने औपचारिक शिक्षा प्राप्त युवाओं को औद्योगिक एवं व्यावसायिक संस्थानों में रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण की सुविधा 'मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना' के तहत लागू की है। इस योजना के अन्तर्गत लाखों युवाओं को "कौशल युक्त" बनाने का लक्ष्य है। इसी तरह कौशल संवर्द्धन एवं आजीविका संवर्द्धन के लिये ज्ञान जागरूकता संकल्प योजना (लघु अवधि प्रशिक्षण हेतु) प्रारंभ की गई है।

(2) राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना – यह भारत सरकार द्वारा संचालित योजना है। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर 6404 प्रतिष्ठानों में दो लाख पचासी हजार तीन सौ पचहत्तर अभ्यर्थियों का पंजीयन किया गया। पंजीयन के पश्चात प्रतिष्ठानों में वर्ष वार प्रशिक्षु शिक्षुओं की संरचना इस प्रकार रही –

क्र.	वर्ष	प्रशिक्षु शिक्षुओं की संरचना
01	2021-22	15267
02	2022-23	20178
03	2023-24	23506

(स्रोत : मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पृ. 256)

(3) पी.एम. विश्वकर्मा योजना – यह योजना केन्द्र सरकार के द्वारा सितम्बर 2023 में शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत 28 परंपरागत व्यवसायों के कौशल को विकसित करने के लिये कौशल प्रशिक्षण देने की योजना है। इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए इस

योजना में प्रदेश के 14 जिलों को भारत सरकार द्वारा चिन्हित किया गया है।

(4) परम (PARAM) फाउण्डेशन – (पी.पी.पी.) निजी, शासकीय भागीदारी मॉडल के तहत विशेष आई.टी.आई. हेतु परम ("पैन आई.टी.आई. एल्युमनाई रीच फॉर मध्य प्रदेश") फाउण्डेशन की स्थापना की गई।

केन्द्र और प्रदेश सरकार 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना को धरातल पर लाने के लिये कार्ययोजना बनाकर कार्य कर रही है। परंतु उक्त तथ्यों के विश्लेषण से ऐसा प्रतीत होता है कि युवाओं की कौशल विकसित करने में कम रुचि है इसके लिये उपाय – वातावरण निर्माण – कौशल विकास कार्यक्रम के लिए गांव में लेकर शहर तक योजना सम्बन्धी जानकारी के डिस्प्ले बोर्ड लगाये जायें, साथ ही एक परिवार से एक युवा को प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाना चाहिए। बेरोजगार युवाओं में दृढ़ संकल्प – देश के युवा सबसे पहले विकसित भारत के लिए संकल्प लें। दूर दृष्टिकोण के साथ विकसित भारत मिशन के लिये प्रशिक्षित हों। कौशल विकसित करें और देश के काम आयें।

नवाचार की ललक – युवाओं को नया सीखने की ललक अपने में पैदा करनी होगी जो प्रतियोगिता से आयेगी। क्योंकि वर्तमान युग – नये क्षेत्र, नई प्रक्रिया, नई उद्योसंरचना एवं नये दृष्टिकोण का है जिससे "मेक इन इंडिया" का स्वप्न पूरा होना है। इसलिए सभी को इसका सारथी बनना पड़ेगा।

संक्षेप में विकसित भारत मिशन, कौशल विकास पर आधारित है। कौशल और हुनर के साथ हमारे युवा नवाचारों, तकनीकी के माध्यम से देश के उपलब्ध प्राकृतिक और वित्तीय संसाधनों का जितना अनुकूलतम प्रयोग करेंगे उतना ही राष्ट्र आगे बढ़ेगा।

"युवा कौशल प्रबंधन में शिक्षित होगा, भारत अवश्य ही विकसित होगा।" □□

(डॉ. जे.पी. मिश्रा, सेवानिवृत्त प्राध्यापक एवं पूर्व कुलसचिव, छतरपुर)

पुण्यस्मरणांजलि: न्यायमूर्ति, लोकमाता अहिल्याबाई होलकर

महारानी, इंसाफ की देवी, जनसरोकारी, अहिल्याबाई होलकर मराठा साम्राज्य की एक प्रसिद्ध शासिका और मालवा क्षेत्र में होलकर राजवंश की संस्थापक थीं। अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई, 1725 को चौंडी गांव, अहिल्यानगर जिला, महाराष्ट्र में हुआ था। उनका विवाह मल्हार राव होलकर के पुत्र खंडेराव होलकर से हुआ था। खंडेराव की मृत्यु के बाद, अहिल्याबाई ने प्रशासन संभाला और अपने राज्य को मजबूत और समृद्ध किया। लोकमाता, अहिल्याबाई होलकर न्याय की ऐसी मूर्ति कि अपने बेटे को भी सजा-ए-मौत का फरमान सुनाने से भी नहीं हिचकीं।

एक बार जब अहिल्याबाई के बेटे मालोजीराव अपने रथ से सवार होकर राजबाड़ा के पास से गुजर रहे थे। उसी दौरान मार्ग के किनारे गाय का छोटा-सा बछड़ा भी खड़ा था। जैसे ही मालोराव का रथ वहां से गुजरा अचानक कूदता-फांदता बछड़ा रथ की चपेट में आ गया और बुरी तरह घायल हो गया। थोड़ी देर में तड़प-तड़प कर उसकी वहीं मौत हो गई। इस घटना को नजरअंदाज कर मालोजीराव आगे बढ़ गए। इसके बाद गाय अपने बछड़े की मौत पर वहीं बैठ गई। वो अपने बछड़े को नहीं छोड़ रही थी।

कुछ ही देर बाद वहां से अहिल्याबाई भी वहां से गुजर रही थी। तभी उन्होंने बछड़े के पास बैठी हुई एक गाय को देखा, तो रुक गईं। उन्हें जानकारी दी गई। कैसे मौत हुई कोई बताने को तैयार नहीं था। अंततः किसी ने डरते हुए उन्हें बताया कि मालोजी के रथ की चपेट में बछड़ा मर गया। यह घटनाक्रम जानने के बाद अहिल्या ने दरबार में मालोजी की धर्मपत्नी मेनाबाई को बुलाकर पूछा कि यदि कोई व्यक्ति किसी की मां के सामने उसके बेटे का कत्ल कर दे तो उसे क्या दंड देना चाहिए? मेनाबाई ने तुरंत जवाब दिया कि उसे मृत्युदंड देना चाहिए।



महारानी अहिल्याबाई
होलकर के जीवन,
समर्पण, न्याय, विकास,
संस्कार और जन
कल्याण के कार्यों को
भारतीय इतिहास में
हमेशा याद रखा
जाएगा। उन्हें शत-शत
नमन!
— हेमेन्द्र क्षीरसागर



इसके बाद अहिल्याबाई ने आदेश दिया कि उनके बेटे मालोजीराव के हाथ-पैर बांध दिए जाएं और उन्हें उसी प्रकार से रथ से कुचलकर मृत्यु दंड दिया जाए, जिस प्रकार गाय के बछड़े की मौत हुई थी। बेटे की जान लेने खुद रथ पर चढ़ गई थीं देवी अहिल्याबाई इस आदेश के बाद कोई भी व्यक्ति उस रथ का सारथी बनने को तैयार नहीं था। तब अहिल्याबाई खुद आकर रथ पर बैठ गई। वो जब रथ आगे बढ़ रही थी, तब एक ऐसी घटना हुई, जिसने सभी को हैरान कर दिया।

वही गाय रथ के सामने आकर खड़ी हो गई थी। जब अहिल्याबाई के आदेश के बाद उस गाय को हटाया जाता तो वो बार-बार रथ के सामने आकर खड़ी हो जाती। यह देख दरबारी मंत्रियों ने महारानी से आग्रह किया कि यह गाय भी नहीं चाहती है कि किसी और मां के बेटे के साथ ऐसी घटना हो। इसलिए यह गाय भी दया करने

पुण्यश्लोक, त्याग की प्रतिमूर्ति, अहिल्याबाई ने मालवा की रानी के रूप में 1737 से 1795 तक शासन किया। उन्होंने हमेशा अपने राज्य और अपने लोगों को आगे बढ़ने का हौंसला दिया। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने प्रजा हित के लिए आगे बढ़ी और सफल दायित्वपूर्ण राजशाही का संचालन करते हुए 13 अगस्त, 1795 को दुनिया को अलविदा कह गई।

की मांग कर रही है। गाय अपनी जगह पर रही और रथ वहीं पर अड़ा रहा। राजबाड़ा के पास जिस स्थान पर यह घटना हुई थी, उस जगह को आज सभी लोग 'आड़ा बाजार' के नाम से जानते हैं।

पुण्यश्लोक, त्याग की प्रतिमूर्ति, अहिल्याबाई ने मालवा की रानी के रूप में 1737 से 1795 तक शासन किया। उन्होंने हमेशा अपने राज्य और अपने लोगों को आगे बढ़ने का हौंसला दिया। आँकारेश्वर पास होने के कारण और मां

नर्मदा के प्रति श्रद्धा होने कारण महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया था। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने प्रजा हित के लिए आगे बढ़ी और सफल दायित्वपूर्ण राजशाही का संचालन करते हुए 13 अगस्त, 1795 को दुनिया को अलविदा कह गई। महारानी अहिल्याबाई होलकर के जीवन, समर्पण, न्याय, विकास, संस्कार और जन कल्याण के कार्यों को भारतीय इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। शत-शत नमन! □□

हेमचंद्र धीरसागर, पत्रकार, लेखक व स्तंभकार

:: सदस्यता संबंधी सूचना ::

मान्यवर,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीऑर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीघ्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि 'स्वदेशी पत्रिका' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है :-

स्वदेशी पत्रिका	वार्षिक	आजीवन
हिन्दी	150 रुपए	1500/- रुपए
अंग्रेजी	150 रुपए	1500/- रुपए

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. **602510110002740, IFSC : BKID-0006025 (Ramakrishnapuram)**

में जमा करवा सकते हैं और उसकी रसीद और अपना पता आप कार्यालय में अवश्य भेजें।

स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर-8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली-22

बेरोजगारी दूर करने को कुटीर उद्योग को बढ़ावा जरूरी

स्वदेशी जागरण मंच जयपुर प्रांत की ओर से विचार वर्ग एवं कार्यशाला का आयोजन समिधा भवन भरतपुर में किया गया। संघ चालक महेंद्र सिंह मग्गो, प्रांत प्रचारक बाबूलाल, मुख्य अतिथि सरदार हिरासिंह, अखिल भारतीय विचार विभाग प्रमुख राजीव कुमार, डॉ. धर्मेन्द्र दुबे, क्षेत्र संयोजक सतीश आचार्य, प्रांत संयोजक सुरेंद्र नामा, प्रांत समन्वयक लोकेंद्र सिंह नरुका ने दीनदयाल उपाध्यय, दत्तोपंत ठेंगड़ी ने भारत माता के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कार्यशाला का शुभारंभ किया।

कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता बाबूलालजी जी ने कहा कि देश को स्वदेशी उत्पादों को आम जन तक पहुंचाने लिये मंच के प्रांत कार्यकर्ता स्वदेशी सुरक्षा एवं स्वावलंबन अभियान चलाकर आम जनता के बीच अलख जगाना है ताकि आमजन स्वदेशी उत्पादों को खरीद कर उपयोग करें जिससे देश विश्व की दूसरी अर्थव्यवस्था को बन सके।

कार्यशाला के मुख्य अतिथि सरदार हीरा सिंह ने कहा कि देश में बेरोजगारी दूर करने के लिये एकमात्र उपाय कुटीर उद्योग धंधों पर ध्यान देना होगा। बेरोजगार युवा सरकारी योजनाओं का लाभ लेते हुए कुटीर उद्योग लगाएं। इससे युवा वर्ग रोजगार युक्त होकर और अपनी आजीविका चलाने में स्वावलंबी बन सकेंगे।

जयपुर प्रांत संघचालक महेंद्र सिंह मग्गो ने कहा कि स्वावलंबी भारत अभियान के कार्यक्रम को पूर्णतया सफल बनाने के लिए प्रत्येक जिला स्तर पर रोजगार सृजन कार्यालय खुलवाना अति आवश्यक है। इससे युवा वर्ग को रोजगार स्थापित करने में आने वाली कठिनाइयों में रोजगार सृजन कार्यालय मददगार साबित होगा।

कार्यशाला को स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख धर्मेन्द्र दुबे, अखिल भारतीय विचार प्रमुख डा. राजीव कुमार, क्षेत्र संयोजक सतीश आचार्य, क्षेत्र समन्वयक अनिल वर्मा, प्रांत संयोजक सुरेंद्र कुमार नामा, प्रांत मन्वयक लोकेंद्र सिंह नरुका, विभाग संयोजक सतीश दीक्षित, राकेश शर्मा, त्रिलोक शर्मा, बलराम बघेल, योगेश दीक्षित, विजय श्रीवास्तव, ओम प्रकाश कोली, भीमसेन कुशवाह, लाखन सिंह, शुभनेश पाराशर, सचिन मित्तल, नरेंद्र बघेल, भागीरथ सिंह, शिवचरण, मेवाराम सैनी, चेतन मीणा, विनीता सिंह, दीप्ति पाराशर सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मंच संचालन प्रांत सहसंयोजक विनोद पाल यादव एवं जिला प्रचार प्रमुख शुभनेश पाराशर ने किया।

विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए स्वजामं का अभियान



स्वदेशी जागरण मंच (एसजेएम) ने लोगों को स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करने के लिए प्रेरित करने और विदेशी सामान का बहिष्कार करने के लिए अभियान आरंभ किया है। स्वदेशी जागरण मंच के आह्वान पर स्वदेशी सुरक्षा एवं स्वावलंबन अभियान के शुरुआत में व्यापारी, उद्योग, व्यवसाय, किसान, श्रमिक, छात्र, धार्मिक, आध्यात्मिक एवं अन्य सामाजिक संगठनों सहित विभिन्न संगठनों के राष्ट्रीय नेताओं ने भाग लिया। सभी ने अभियान के प्रति अपनी एकजुटता और सक्रिय समर्थन व्यक्त किया।

एसजेएम के राष्ट्रीय सह संयोजक डॉ. अश्वनी महाजन ने कहा कि अभियान को शुरू करने का यह उपयुक्त समय है। जिसमें भारत के सभी नागरिकों से विदेशी वस्तुओं और सेवाओं के उपयोग का बहिष्कार करने और स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया गया है। उन्होंने कहा कि अभियान में व्यापारियों से भी आह्वान किया गया कि वे विदेशी वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार न करें।

अभियान के दौरान ऑपरेशन सिंदूर की शानदार सफलता की सराहना की गई, जिसमें हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान, पीओजेके क्षेत्रों में स्थित आतंकवादी ठिकानों और लांच पैड को नष्ट कर दिया तथा हमारे स्वदेशी रूप से विकसित और उत्पादित रक्षा उपकरणों से उनके एयरबेस और डिपो को नष्ट कर दिया। लोगों ने चीनी और तुर्की की सभी वस्तुओं का बहिष्कार करने का आह्वान किया। स्वदेशी जागरण मंच ने सभी देशवासियों से सामान्य रूप से सभी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का आह्वान किया, लेकिन चीनी और तुर्की वस्तुओं का बिल्कुल भी बहिष्कार करने का आह्वान किया।

महाजन ने बताया कि कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन द्वारा टैरिफ बढ़ाने, गैर-अमेरिकी मूल के लोगों द्वारा भेजे जाने वाले धन पर कर लगाने के परिदृश्य को देखते हुए, स्वदेशी जागरण मंच ने देश के लोगों से विदेशी फंडिंग वाली अमेजन, पिलपकार्ट-वॉलमार्ट जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों का बहिष्कार करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी जागरण मंच भारत सरकार से

अनुरोध करेगा कि वह रॉयल्टी, लाभांश, तकनीकी शुल्क, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों पर भी ध्यान दें।

<https://www.navodayatimes.in/news/national/swadeshi-jagran-manch-campaign-to-boycott-foreign-goods/267409/>

तुर्किये और अजरबैजान के राष्ट्रपति का पुतला फूँका



मुरादाबाद जिले के व्यापारियों में तुर्किये के पाकिस्तान को समर्थन देने से रोष है। इसे लेकर स्वदेशी जागरण मंच और अन्य व्यापार मंडलों के पदाधिकारियों ने इंपीरियल तिराहे पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पदाधिकारियों ने तुर्किये और अजरबैजान के राष्ट्रपति का पुतला फूँककर दोनों देशों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही आर्थिक बहिष्कार करने का आह्वान किया।

तुर्किये और अजरबैजान के विरोध में विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता हाथ बैनर, पोस्टर लेकर इंपीरियल तिराहे पर एकत्रित हुए। स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय विचार विभाग प्रमुख डा. राजीव कुमार ने कहा कि जिस प्रकार युद्ध में तुर्किये और अजरबैजान ने पाकिस्तान की मदद की है। हम संकल्प लेते हैं कि इन देशों का संपूर्ण रूप से आर्थिक बहिष्कार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के हरीश भसीन ने कहा कि व्यापारियों का संकल्प है कि तुर्किये के साथ कोई भी व्यापार नहीं किया जाएगा।

स्वदेशी जागरण मंच के प्रांत संयोजक कपिल नारंग ने आतंकवादियों को शहीद बताने वालों का बहिष्कार करने का आह्वान किया। प्रशांत शर्मा, हिमांशु मेहरा, डा. एके अग्रवाल, विपिन भट्ट, अधिवक्ता नीरज सोलंकी, प्रदीप शर्मा, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल से दीपक अग्रवाल, अपूर्व अग्रवाल, सचिन वर्मा, सुरेंद्रनाथ राहुल खन्ना, यूपी उद्योग व्यापार मंडल से हरीश भसीन, व्यापारी सुरक्षा फोरम से विजय मदान, अमित अग्रवाल, कौशल टंडन, संजीव गुप्ता, मयूर भाटिया, गुरप्रीत सिंह दुआ, कुशल टंडन आदि मौजूद रहे।

विदेशी सामान की होली जलाकर दिया स्वदेशी अपनाने का संदेश

स्वदेशी जागरण मंच अजयमेरु (अजमेर) के तत्वावधान में कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी सर्किल पर विदेशी सामान की होली जलाई गई। स्वदेशी जागरण मंच महानगर संयोजक योगेंद्र सिंह गोयला ने बताया कि वर्तमान में संपूर्ण देश ऑपरेशन सिंदूर पर गर्व का अनुभव कर सेना के शौर्य को सलाम कर रहा है। ऐसे में स्वदेशी जागरण मंच ने नागरिकों को विदेशी सामानों की होली जलाकर संदेश दिया है कि वह पाकिस्तान का समर्थन करने वाले तुर्की, अजरबैजान और चीन के सामानों का बहिष्कार कर इन देशों के आर्थिक रूप से कमर तोड़े।



विभाग सहसंयोजक डॉ. कुलदीप सिंह ने बताया कि आर्थिक रूप से भारत विरोधी पाकिस्तान का समर्थन करने वाले चीन, तुर्की और अजरबैजान के समान भारतीय घरों से दूर हो और यहां का स्वदेशी सामान अपनाएं। इससे भारत विकास की ओर अग्रसर होगा अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। महानगर संयोग का डॉक्टर सुचिता राठौर ने बताया कि आज ऑपरेशन सिंदूर में भारत की प्रत्येक नारी अपना योगदान निभा सकती है। भारत की जागरूक नारी घर में आने वाले प्रत्येक विदेशी सामान का बहिष्कार कर स्वदेशी सामान अपनाकर राष्ट्रभक्ति और देश प्रेम का परिचय दे सकती हैं।

कार्यक्रम के दौरान गरिमा गोयल ने बताया कि कार्यक्रम में शहर के विविध संगठनों का सहयोग रहा। इस अवसर पर स्वदेशी जागरण मंच चित्तौड़ प्रांत संयोजक डॉ. संत कुमार, उप महापौर नीरज जैन, अरविंद शर्मा, तिलक सिंह रावत, दिनेश शर्मा, सर्वेश बजाज सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

शिक्षा केवल नौकरी के लिए नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता के लिए: केशव

स्वदेशी जागरण मंच के मध्यक्ष संगठक केशव दुबौलिया के मुख्य आतिथ्य में 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का भारत केंद्रित क्रियान्वयन तथा स्वावलंबी भारत' विषय पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक मध्य प्रदेश में किया गया। कार्यक्रम में अधिष्ठाता, विभाग अध्यक्ष, विश्वविद्यालय के अनेक शिक्षकों, स्वदेशी कार्यकर्ता तथा स्नातक-स्नातकोत्तर एवं पीएचडी के छात्र-छात्राएं सम्मिलित हुए।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केशव दुबौलिया ने कहा कि शिक्षा केवल नौकरी के लिए नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता के लिए होनी चाहिए। शिक्षा केवल जानकारी देने का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मबल, चरित्र, स्वावलंबन और राष्ट्रनिर्माण का आधार होनी चाहिए।



राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत केन्द्रित दृष्टिकोण को पुनः स्थापित करने का ऐतिहासिक अवसर है। भारत को आत्मनिर्भर तथा विकसित बनाने के लिए यह आवश्यक है कि हमारी शिक्षा प्रणाली रोजगार मांगने वालों को नहीं, बल्कि रोजगार देने वालों को तैयार करे। इंटरनशिप और प्रायोगिक अनुभव आधारित शिक्षा, जिससे छात्र समस्याओं को समाधान में बदल सकें। विश्वविद्यालयों और स्वदेशी महाविद्यालयों में स्टार्टअप और नवाचार आधारित उद्यमिता विकास के लिए शिक्षण संस्थाओं में 'स्वावलंबन - केंद्र' की स्थापना होना परम आवश्यक है। ग्रामीण, जनजातीय और पिछड़े वर्गों के लिए स्थानीय संसाधनों पर आधारित स्वावलंबन के अवसर के साथ हर विद्यार्थी को यह आत्मविश्वास मिलना चाहिए कि वह स्वयं निर्माण कर सकता है, नेतृत्व कर सकता है और समाज के लिए कुछ कर सकता है। यही सच्चा क्रियान्वयन होगा।

‘विदेशी छोड़ो, स्वदेशी अपनाओ’ अभियान के तहत निकाली रैली



स्वदेशी जागरण मंच जमशेदपुर महानगर द्वारा 'विदेशी छोड़ो, स्वदेशी अपनाओ' अभियान को जनआंदोलन का स्वरूप देने के लिए साकची में एक रैली निकाली गई। जिसमें लगभग 80 स्वदेशी समर्थक शामिल हुए। रैली के दौरान "वालमार्ट बायकाट", "अमेजन बायकाट", "चीनी कंपनियां भारत छोड़ो", जैसे गगनभेदी नारों से साकची गूंज उठा। रैली के बाद खादी ग्रामोद्योग आयोग के पूर्वी भारत के चेयरमैन मनोज सिंह ने कहा, "स्वदेशी अपनाने से देश में रोजगार और आत्मनिर्भरता दोनों का विकास होगा। विदेशी कंपनियों का बहिष्कार देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा।" उन्होंने इसे राष्ट्र निर्माण का अभियान बताया।

बन्देशंकर सिंह ने कहा कि विश्व व्यापार युद्ध के इस दौर में भारत की रक्षा और उन्नति का मार्ग सिर्फ स्वदेशी है। रैली में जटा शंकर पांडेय, अमित मिश्रा, पंकज सिंह, मधुलिका मेहता, मंजू ठाकुर, राज कुमार शाह, राजेश बरनवाल, हरप्रीत कौर, सुमित सिंह, प्रवीण सिंह, रश्मि साहू आदि उपस्थित रहे।

जमशेदपुर महानगर की संयोजक राजपति देवी के नेतृत्व में साकची चौक से बाजार तक रैली का आयोजन कर 'विदेशी छोड़ो, स्वदेशी अपनाओ' के विषय को समाज में लाने का काम किया। रैली में 80 से अधिक सदस्य शामिल हुए। स्वदेशी कार्यकर्ताओं ने बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत छोड़ो, जब बाजार जायेंगे- सामान स्वदेशी लायेंगे, विदेशी वस्तु धोखा है, बहिष्कार करो मौका है, जैसे नारे लगाये। रैली के बाद साकची में नुक्कड़ सभा को खादी ग्रामोद्योग आयोग के मनोज सिंह, बंदे शंकर सिंह, सुबोध श्रीवास्तव, जीतू सिंह, जटाशंकर पांडेय, अमित मिश्रा, राजकुमार शाह, अभय सिंह, अखिल सिंह व पंकज सिंह ने भी संबोधित किया। जिला संयोजक राजपति देवी ने कहा कि भारत को आर्थिक प्रगति के मार्ग पर बढ़ाने का एक ही मार्ग है वह है- स्वदेशी। स्वदेशी जागरण मंच जिस विषय पर पहले भी आग्रह रखता रहा है, उसे अब प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधनों में सार्वजनिक रूप से रखना सिंह; किरण जीत कौर, राजेश प्रारंभ किया है। □□

स्वदेशी गतिविधियां

प्रांतीय विचार वर्ग

सचित्र झलक



मालवा



जम्मु



सौराष्ट्र



जयपुर



महाकौशल



स्वदेशी गतिविधियां विदेशी वस्तुओं/सेवाओं के खिलाफ प्रदर्शन

सचित्र झलक



दिल्ली



प्रयागराज



राजपुरा, पंजाब



धीलपुर



देवघर, झारखंड



गुवाहाटी, असम



काशी



भुवनेश्वर, उड़ीसा



बिपुरा



सीतागढ़, बिहार



मुरादाबाद



लुधियाना, पंजाब



भीलवाड़ा



गुजरात



बागपत, यू.पी.



जयपुर



कोरियापुर, उड़ीसा



जमशेदपुर, झारखंड

प्रकाशक व मुद्रक डॉ. अश्वनी महाजन द्वारा स्वदेशी जागरण समिति के लिए काम्प्यूटेंट बाईन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली से मुद्रित और धर्मक्षेत्र, सेक्टर-8, रामाकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली-110022 से प्रकाशित, संपादक: अजेय भारती